मासिक समाचार पत्र

लोकविद्या पंचायत

● सूचना युग में बराबरी के विचार के पुनर्निर्माण का पत्र ●
● लोकविद्याधर समाज के पुनर्संगठन का वैचारिक आधार पत्र ●
● पूँजी आधारित समाज के स्थान पर ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का विचार पत्र ●

प्रकाशन का स्थान : विद्या आश्रम, सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007

वर्ष 1, अंक 10-11, कुल पृष्ठ : 8 | फरवरी-मार्च 2012 | सहयोग राशि : 5 रुपये

भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का संघर्ष

1 मार्च 2012 को हरियाणा के पीपली में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने की माँग को लेकर लगभग 15000 किसानों ने हाईवे नं. 1 पर इकट्ठा होकर जाम लगा दिया। किसानों ने

हाईवे पर बैठकर लगभग 5-6 घंटे तक आवा-जाही बाधित कर दी। पुलिस ने कई हजार किसानों को गिरफ्तार किया। बाद में किसान रैली बनाकर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आगे बढ़े लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कृषि मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री से बात कराने के आश्वासन पर किसानों ने जाम खत्म किया।

दूसरे दिन मुख्यमंत्री से किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है जिसके चलते किसान बार-बार आन्दोलन करने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से तारीख पक्की कर किसान यूनियन के नेताओं से बात कराने की जिम्मेदारी ली।

(भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह से वार्ता के आधार पर)

फुटकर धंधे में विदेशी निवेश के खिलाफ दिल्ली में विरोध रैली

22 फरवरी 2012 को देशभर से आये हजारों व्यापारियों और दुकानदारों ने भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के बैनर तले दिल्ली में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन फुटकर धंधे में 51 फीसदी बाहरी पूंजी निवेश को मंजूरी देने के सरकारी प्रयासों के खिलाफ था। विभिन्न प्रांतों से आये व्यापारी सुबह-सुबह ही जंतर-मंतर पर इकट्ठा होना शुरू हो गये। बाद में जब उन्होंने संसद भवन की ओर कूच किया, संसद मार्ग पुलिस थाने द्वारा बेरीकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया। केरल व्यापारी व्यवसायी एकोपना समिति के नेतृत्व में केरल से 5000 दुकानदारों व व्यापारियों ने भाग लिया।

नेताओं ने प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार तमाम विरोध के बावजूद मनमाना करने पर उतारू है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और बड़ी विदेशी पूंजी को फुटकर धंधे पर कब्जा नहीं करने देंगे। इससे केवल फुटकर धंधा ही नहीं बल्कि कृषि और खाद्य सुरक्षा दोनों बरबाद हो जायेंगे। केरल से आये नेता श्री नजीरूद्दीन ने कहा कि केरल की सरकार फुटकर धंधे में विदेशी पूंजी का निवेश रोक रही है लेकिन केन्द्र सरकार उन पर लगातार दबाव ला रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और दिल्ली इन सभी राज्यों के व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रदर्शन और जुलूस में भाग लिया। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी मिश्रा ने कहा कि हिन्दुस्तान के फुटकर धंधे और कृषि पर इस कब्जे के खिलाफ हम अपना आंदोलन तेज करेंगे।

वाराणसी में नई शुरुआत

विद्या आश्रम पर लोकविद्या ताना-बाना का उद्घाटन : 19 फरवरी, 2012

यह एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है। सूचना और सम्पर्क की दुनिया में लोकविद्याधर समाज अपना स्थान हासिल करे इसकी शुरुआत है। सूचना और सम्पर्क के लोकविद्या समाज के जो अपने तरीके हैं, उनकी जो अपनी विधायें हैं उनमें ताकत भरने की यह एक

खोज है। इसकी भी खोज है कि उनकी ताकत का परिचय सार्वजनिक दुनिया को कैसे कराया जाय। हमने किसानों के संघर्ष में यह पाया है कि कभी-कभी उन गांवों के नवयुवक अपने मोबाइल पर संघर्षों का विडियो रेकार्ड कर लेते हैं। पुलिस की आततायी कार्यवाही भी रेकार्ड कर लेते हैं। वे इसमें अपने समाज से अपनी लगन, उत्साह, हिम्मत, जानकारी और समझ इस सबका परिचय देते हैं। इसी वास्तविकता की पहचान से लोकविद्या जन आंदोलन का यह प्रयास शुरू होता है।

19 फरवरी को विद्या आश्रम के परिसर पर गांवों के नवयुवकों के लिये एक मीडिया शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उनका परिचय लोकविद्या विचार और मीडिया की तकनीकों से कराया गया। साथ में 'लोकविद्या ताना-बाना' के नाम से इसी विषय पर व्यापक वार्ता का आयोजन किया गया। दोनों की रिपोर्ट पृष्ठ 5 पर दी गई है।

लोकविद्या जन आंदोलन के बढ़ते कदम

मालवा और मिथिला के प्रस्तावित कार्यक्रम

भोपाल और इन्दौर में 23 से 26 मार्च के बीच निम्नलिखित कार्यक्रम होने जा रहे हैं :

1. 23 मार्च 2012
लोकविद्या और डॉ. लोहिया की दृष्टि
स्थान : विधायक निवास, खण्ड-2, सभा हॉल, भोपाल
समय : दोपहर 3.00 बजे से
सम्पर्क : अवधेश 9425013524

2. 25 मार्च 2012
लोकविद्या और विस्थापन
- लोकविद्याधर समाज ही क्यों विस्थापित होता है!
- लोकविद्याधर समाज की स्थापक एकता में ही विस्थापन का जवाब है।

स्थान : पीथमपुरा, इन्दौर
समय : सुबह 9.00 बजे से

3. 25 मार्च 2012
लोकविद्या जन आंदोलन में मीडिया की भूमिका
भाषा, कला, दर्शन और लोकविद्या ताना-बाना पर वार्ता
स्थान : विसर्जन आश्रम, नवलखा, इन्दौर
समय : शाम 5.00 बजे से

4. 26 मार्च 2012
सभी के लिए नियमिति आय की पक्की व्यवस्था हो
- लोकविद्या के आधार पर पक्की नौकरी मिले
- वेतन सरकारी कर्मचारी के बराबर हो

स्थान : ग्राम-पालडि, जिला इन्दौर
समय : सुबह 9.00 बजे से

इन्दौर सम्पर्क :
मगनसिंह बघेल, मो. 8085213714

इन्दौर में बाजार मोड़ो अभियान

बिहार में लोकविद्या जन आंदोलन का अधिवेशन

31 मार्च–1 अप्रैल 2012, स्थान : जिला परिषद हाल, लहरिया सराय, दरभंगा

मिथिला के चार जिलों—मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल में लोकविद्या जन आंदोलन का कार्य शुरू हो गया है। गांव-गांव में सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कितने तरह के ज्ञान लोगों के पास हैं, जिनके बल पर वे अपनी जीविका चला रहे हैं। लोकविद्या जन आंदोलन ने यह मांग की है कि हर व्यक्ति के पास निश्चित आय के स्रोत होने चाहिए। हर व्यक्ति को लोकविद्या के आधार पर, यानि उसे जो आता है उसके बल पर पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। और इस नौकरी में उसकी तनख्वाह सरकारी कर्मचारी के बराबर होनी चाहिए। मिथिला प्रदेश नदियों का प्रदेश है। नदियों के पानी का उचित प्रबंधन और कृषि की प्रणाली पर सही सोच के बगैर वहां की समस्याओं का कोई हल नहीं है। न पलायन का हल है और न गरीबी का।

लोकविद्या जन आंदोलन का यह अधिवेशन यह दृष्टिकोण सामने लायेगा और इसके लायक कार्यक्रम बनायेगा कि किस तरह लोकविद्या के अंतर्गत समाधान पाया जा सकता है। इस अधिवेशन में शरीक होने के लिए सभी आमंत्रित हैं।

विजय कुमार लोकविद्या जन आंदोलन के बिहार समन्वयक हैं और इस अधिवेशन के प्रमुख संयोजनकर्ता (मो. 0943106855)।

विस्थापन रोको और बाजार मोड़ो

संजीव कीर्तने, इन्दौर

मध्य प्रदेश के पश्चिम के हिस्सों, खासकर इन्दौर, देवास, निमाड़, धार, झाबुआ, रतलाम में विकास के नाम पर कई ऐसी योजनाओं को प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके चलते बड़ी संख्या में किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदार और इन सबकी महिलाएं और इनके परिवार उजाड़ का शिकार हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, शहरों का विस्तार, बड़े बांधों का निर्माण, रेल पटरियां और फोरलेन का निर्माण, उच्च शिक्षण संस्थानों, मेडिकल हब, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और कम्प्यूटर की बड़ी-बड़ी कंपनियों को लाकर ऐसा आभास देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसी एकमात्र विकास के दृष्टिकोण से इन अंचलों के लोगों को रोजगार मिलेगा और इनकी गरीबी दूर हो जायेगी। इस विकास को राजनैतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और देश की बड़ी राजनैतिक पार्टियां भी खुलकर इस विकास के समर्थन में जनभावनाओं को कुचल रही हैं।

ग्राम-पालडी, जिला-इन्दौर में लोकविद्या बैठक

पश्चिमी मध्य प्रदेश के इन हिस्सों में लोगों ने इस विकास की धारणा का खुलकर विरोध किया है और जगह-जगह छोटे-छोटे संघर्ष खड़े किये हैं। लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि केवल किसान, कारीगर, आदिवासी और छोटे-छोटे दुकानदार ही उजाड़े जा रहे हैं। ये सभी लोकविद्याधर हैं और अपनी विद्या यानि लोकविद्या के आधार पर सदियों से जीते आ रहे हैं और इन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि जो-जो लोग लोकविद्या के आधार पर जी रहे हैं उन्हें ही विस्थापित किया जा रहा है। शायद लड़ाई अब लोकविद्या और संगठित विद्या के बीच हो रही है विकास का सारा लाभ संगठित विद्या के क्षेत्र को है तथा विनाश लोकविद्याधर समाज का है।

इन अंचलों के लोगों से बात करते हैं तो यही समझ में आता है कि किसान बुरी तरह से परेशान हैं, कारीगरों के धंधे राक्षसी बाजार तंत्र ने छिन्न-भिन्न कर दिये हैं, आदिवासी अपना गांव छोड़ने पर मजबूर है और छोटे-छोटे दुकानदार बड़ी कंपनियों के उत्पादों को उनकी शर्तों पर बेचने को मजबूर हैं। गांव के युवा दिन रात यही सोचते हैं कि जैसे भी हो एक छोटी-सी सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल जायेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

विस्थापन रोको-बाजार मोड़ो अभियान का प्रारम्भ इन्हीं लोकविद्याधरों की सोच का परिणाम है। लोकविद्याधरों के संघर्षों को लोकविद्या के दृष्टिकोण से समझने पर ऐसी सम्भावनाएं उजागर हुई हैं जो किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदारों और इनकी महिलाओं को एक सूत्र में बांध सकेंगी और इनकी महाएकता को स्थापित कर सकेंगी। एक ऐसे विचार के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है जो इनके छोटे-छोटे संघर्षों को समझ सके और फिर इनमें आपसी समन्वय स्थापित करके एक बड़े परिवर्तनकारी संघर्ष के रूप में आकार ले। लोकविद्याधर समाज के पुनर्संगठन का विचार और उनकी एकता के विचार का पुनर्निर्माण करने के लिए पूरे देश में लोकविद्या जन आंदोलन की शुरुआत हुई है। यह लोकविद्याधर समाज का ज्ञान आंदोलन है। विस्थापन रोको-बाजार मोड़ो अभियान चलाने के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोकविद्या समन्वयक समिति का गठन भी किया गया है।

भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग और लोक उपक्रम मंत्रालय द्वारा ऑटो टैस्टींग ट्रेक की स्थापना हेतु आबादी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। नवीन बेटमा पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल क्लस्टर में मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विकास में भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना और विस्तार से कई गांव प्रभावित हुए हैं। इस पूरे क्षेत्र में लगातार विस्थापन हो रहा है। किसान संघर्ष समितियां बनाकर कई गांवों ने विरोध किया है और निरंतर संघर्षरत हैं। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत जिला इन्दौर ने भी धरना आंदोलन किया है। इन्दौर के अनेक राजनैतिक पार्टियों ने, समाजसेवी संस्थाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। सुश्री मेधा पाटकर की भी सभाएं हुई हैं। लोकविद्याधारी हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी गये हैं।

किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदार विस्थापन रोकने के लिए कहां-कहां नहीं गए हैं। वर्तमान व्यवस्था के हर प्रभावशाली तंत्र और प्रभावशाली व्यक्तियों को गुहार लगा चुके हैं और उन्हें निराश ही होना पड़ा है। लोकविद्या दृष्टिकोण से ज्ञान को केन्द्र में रखकर यदि पूरे मसले पर दृष्टि डाली जाये तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि यह तो ज्ञान के सवाल पर ही टकराव है। एक तरफ वे लोग हैं जो समाज से सीखते हैं, जो लोकविद्याधारी हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो विश्वविद्यालयीय और अन्य संगठित विद्या के बल पर जीते हैं और वर्तमान शोषण की व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत बनाये जा रहे हैं। लोकविद्याधरों को यह दावा पेश करना होगा कि वे लोकविद्या के बल पर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटे-छोटे दुकानदार और इन सबकी महिलाओं और परिवारों की एकता में ही शोषणमुक्त समाज बनाने की कुंजी है। ऐसा स्पष्ट होता दिखाई देने लगा है।

इन्दौर के आसपास के गांवों में 'लोकविद्या बाजार बनाओ' का अभियान चलाकर निम्नलिखित मुद्दों पर सघन वार्ता और बैठकें आयोजित की गई हैं और लोकविद्या बाजार के स्वरूप को सामने लाने का प्रयास किया गया।

- लोकविद्या बाजार शहरों और गांवों से संचालित होगा।
- इसमें सभी लोग अपने ज्ञान और श्रम के बल पर निर्माण/उत्पादन करेंगे।
- ये बाजार आपसी लेन-देन के स्थान बनेंगे न कि मुनाफा कमाने के लूटतंत्र।
- इसमें शिक्षा (स्कूल, कॉलेज इत्यादि) और स्वास्थ्य (अस्पताल इत्यादि) सेवा के क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें मुनाफा कमाना गैर-कानूनी होगा।
- इसमें किसानों के अनाज, सब्जी, दूध को लाभकारी दाम मिलने की गारण्टी होगी।
- इसमें वस्त्र और खाद्य पदार्थों के उत्पादन-विक्रय का कार्य केवल स्त्रियों के पास होगा।
- इसमें छोटी दुकानदारी में बिकने वाली वस्तुएं बड़े दुकानदार नहीं बेचेंगे।
- इसमें मजदूरी की न्यूनतम दर वही होगी जो सरकारी नौकरी के न्यूनतम वेतन में होती है।

उपरोक्त कुछ ठोस बिन्दुओं के साथ लोकविद्या बाजार बनाने की पहल की जा रही है। एक साइकिल रिक्शा पर लोकविद्या साहित्य भी इन गांवों में ले जाया जाता है।

ज्ञान पंचायत

अभियान की ओर से इनमें से कुछ गांवों में चित्र में दिखाई गई पांच खम्भों पर खड़ी मड़ई का निर्माण किया है। इस मड़ई का प्रत्येक खम्भा लोकविद्याधर समाज के पांच प्रमुख अंगों (किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटा दुकानदार और महिलाएं) में से एक को दर्शाता है। यह मड़ई उस गांव की 'ज्ञान पंचायत' है। यहीं पर बैठकर गांव के लोग अपनी विद्या/ज्ञान और समाज पर विचार करते हैं।

इसी के साथ कुछ गांवों में लोकविद्या के बल पर रोजगार के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस बात पर बहस छेड़ी गयी कि लोकविद्या के बल पर यानि जिसे जो आता है उसके बल पर उसे पक्की आमदनी (वेतन) का बन्दोबस्त हो। यह वेतन सरकारी वेतन से कम न हो। इस मुद्दे पर सहमति रखने वाले लोकविद्याधरों ने हस्ताक्षर करके इस अभियान को गति दी।

इन्हीं गांवों में एक कला-यात्रा भी मार्च 2012 में निकालने की योजना है।

•

युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर

10-11 दिसंबर, 2011 : सिंगरौली

स्थानीय कार्यकर्ताओं की पहल पर आयोजित इस दो दिवसीय शिविर में युवाओं और स्त्रियों की भूमिका अधिक रही। पिछले कुछ वर्षों से बिजली उत्पादन, कोयला खनन और धातु उद्योग के क्षेत्रों में सिंगरौली जिले में बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों के अनेक उपक्रम शुरू हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार इन्हीं उपक्रमों का हर कदम पर पक्ष लेते हैं। नतीजेस्वरूप वहां इन वर्गों का प्रकृति और मनुष्य दोनों के प्रति बेहद आक्रामक रूप है। विस्थापन और विस्थापन के चलते और मजदूरों के शोषण के चलते रोज-रोज नये-नये स्थानों पर संघर्ष खड़े होते रहते हैं। विद्या आश्रम ने अब काफी समय से वहां पहल लेकर लोकविद्या दृष्टिकोण से संघर्षशील कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाया है और एक व्यापक एकता की खोज जारी रखी है। इसी खोज के अंतर्गत इस शिविर का आयोजन किया गया है। शिविरार्थियों को मुख्य रूप से लोकविद्या जन आंदोलन के विचार से अवगत कराया गया। यह समझाया गया कि स्थानीय संघर्षों को एकजुट करने के लिए पूरे क्षेत्र की बहुआयामी समस्या को केन्द्र में रखना होगा, विस्थापन, मजदूरों का शोषण और पर्यावरण के मुद्दों के साथ यह जोड़ना होगा कि लोकविद्या के आधार पर सभी की आय सुनिश्चित होना जरूरी है।

लोकविद्या प्रशिक्षण शिविर

शिविर को मुख्य रूप से अवधेश, सुनील, चित्रा, मंजू सिंह, पन्नेलाल यादव, लक्ष्मी चंद दुबे और अजय ने सम्बोधित किया। प्रतिभागियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। संघर्षकर्ताओं के बीच तथा संघर्षकर्ताओं के आम समुदाय के साथ संपर्क में विकास के लिए एक स्थानीय प्रयास पर चर्चा हुई। लोकविद्या मीडिया के रूप में एक अपने नाम से, जैसे 'सिंगरौली डुग्गी', नया प्रयास शुरू करने की सम्भावना पर चर्चा की गई। शिविर का आयोजन सृजन लोकहित समिति के बैढ़न परिसर में हुआ।

•

लोकविद्या प्रपंचम्

(लोकविद्या का तेलुगु प्रकाशन)

लोकविद्या जन आंदोलन के आन्ध्र प्रदेश समूह ने इस वर्ष 'लोकविद्या प्रपंचम्' (लोकविद्या की दुनिया) के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया है। अभी तक 3 अंक निकल चुके हैं। पहला अंक 1 जनवरी 2012 को हैदराबाद के केन्द्रीय बस अड्डे पर पास के जिले के एक गांव जा रही बस में लोकार्पित किया गया। दूसरा अंक 16 जनवरी 2012 को दुबाक (जिला मेदक) से प्रसारित किया गया और तीसरे का प्रसारण 16 फरवरी को रंगारेड्डी जिले के याचाराम के पास के गांव नन्दीवनपर्ती से शुरू किया गया। हरेक जगह पर एकत्रित लोगों के बीच एक स्थानीय व्यक्ति ने पत्रिका को समाज के प्रति समर्पित किया।

इन अंकों में लोकविद्या, लोकविद्या जन आंदोलन, हथकरघा, बुनकरों की समस्याओं पर लोकविद्या का नजरिया, फुटकर धंधे में विदेशी निवेश, तेलंगाना आंदोलन, पिछड़ापन, पर्यावरणीय सुरक्षा आदि विषयों पर लेख छपे हैं। तीसरे अंक में लोकविद्या पर एक उर्दू लेख है। पत्रिका के सम्पदक टी. नारायण राव हैं।

हम इस पत्रिका के मार्फत आन्ध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लोकविद्या और लोकविद्या ताना-बाना के विषयों पर संवाद चलाना चाहते हैं और इसके माध्यम से लोगों को जोड़कर इस वर्ष आगे चलकर आन्ध्र प्रदेश में लोकविद्या जन आंदोलन का एक अधिवेशन करना चाहते हैं। तेलुगु में लोकविद्या पुस्तक का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है।

–बी. कृष्णराजुलु, हैदराबाद

लोकविद्या जन आंदोलन, बिहार

दो दिवसीय शिविर : 17-18 दिसंबर, 2011, स्थान : ग्राम चनौर, प्रखण्ड मनीगाछी, जिला-दरभंगा

सुनील कुमार मण्डल, मधुबनी

शिविर में पहले से परिचित मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल जिलों के कुल 50 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जिनमें छः स्त्रियों भी शामिल रहीं। समय-समय पर वक्ताओं की बात सुनने के लिए गांव के स्त्री-पुरुष भी शिविर-स्थल पर इकट्ठा होते रहे।

शिविर की शुरुआत स्थानीय वरिष्ठ किसान कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने सभी के स्वागत के साथ की। शिविर के संयोजक तथा लोकविद्या जन आंदोलन के बिहार समन्वयक विजय कुमार ने विद्या आश्रम, वाराणसी से आये सुनील सहस्त्रबुद्धे और डॉ. चित्रा सहस्त्रबुद्धे का परिचय कराया और सभी भागीदारों से परिचय के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लोकविद्या जन आंदोलन एक नया विषय लग सकता है लेकिन वास्तव में यह हमारे ही गांव-घर की बात है। आज जो ज्ञानी है और अपने ज्ञान के बल पर अपने परिवार और समाज का जीवन चलाता है उसे ही हाशिये पर डाल दिया गया है। किसान, कारीगर, बुनकर, मोची, बढ़ई, कुम्हार और सभी समुदायों के लोगों के ज्ञान को ही लोकविद्या कहा जाता है। लोकविद्या जन आंदोलन इन्हीं समुदायों का ज्ञान आंदोलन है। यही बात समझने और समझाने का प्रयास इस शिविर में किया जायेगा।

सुनील सहस्त्रबुद्धे ने लोकविद्या के विषय पर विस्तार से बात की और यह निष्कर्ष निकाला कि लोकविद्याधर समाज के कष्ट दूर करने का एक ही तरीका है, वह यह कि सभी लोगों को, उन्हें जो आता है उसके बल पर पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, एक ऐसी नौकरी जिसमें वेतन और अन्य व्यवस्थाएं सरकारी नौकरियों के बराबर हो। उन्होंने लोकविद्या और विश्वविद्यालय के ज्ञान का एक तुलनात्मक अध्ययन सामने रखा और दिखाया कि दुनिया जब तक विश्वविद्यालय के ज्ञान को आधार बनाएगी उल्टी ही खड़ी रहेगी जैसा कि अभी है और यह कि लोकविद्या के आधार पर ही दुनिया अपनी मानवता वापस प्राप्त कर सकती है।

डॉ. चित्रा सहस्त्रबुद्धे ने यह समझाया कि किस तरह लोकविद्या जन आंदोलन समाज में लोकविद्या का दावा पेश करने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के ज्ञान को चुनौती देनी होगी, अपना सिर उठाकर खुलेआम यह कहना होगा कि हम ज्ञानी हैं, हमारे पास जीने और समाज को व्यवस्थित रखने की कला और कौशल है। अपनी भाषा है। अपनी समझदारी है, अपने तर्क और अपने मूल्य हैं, जिन सबके बल पर हम कृषि करते हैं, उद्योग चलाते हैं, पेड़-पौधों का संरक्षण करते हैं, अपने घर और परिवार बनाते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और अपने सामाजिक सम्बन्धों का सतत पुनर्निर्माण करते रहते हैं। तुम्हारा ज्ञान, विश्वविद्यालय का ज्ञान, झूठा है, शोषणकारी है, अमानवीय है, प्रकृति को नष्ट करता है। अब न हम दबने वाले हैं और न तिरस्कार सहने वाले हैं। लोकविद्या में वह विस्तृत आधार है जिसके बल पर हम अपनी लड़ाइयां लड़ेंगे, जीतेंगे और नई दुनिया बनायेंगे। यही हमारा ज्ञान आंदोलन है, उन लोगों का ज्ञान आंदोलन

विजय कुमार शिविर को सम्बोधित करते हुए

है जिन्हें तुम अनपढ़ और गंवार कहते हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी हैं। चित्राजी ने सरकार की उन नीतियों का भी खुलासा किया जिसके चलते चारों तरफ विस्थापन हो रहा है और पूंजीपतियों को सस्ते में मजदूर उपलब्ध हो रहे हैं।

पहले दिन की दोपहर तक विद्या आश्रम के दिलीप जी भी शिविर स्थल पर पहुंच गये थे। वे भारतीय किसान यूनियन के वाराणसी मंडल के सचिव भी हैं। उन्होंने विशेषकर किसानों की बात की। हरित क्रांति के बाद चले दौर पर चर्चा की और कहा कि छोटा किसान बरबाद हो गया। महंगी तकनीक, महंगी लागत और अब उदारीकरण ने कृषि और किसान दोनों को बरबाद कर दिया। लोकविद्या जन आंदोलन एक किसान आंदोलन है। यह गांधी और जेपी की निरंतरता का आंदोलन है।

शाम के वक्त 3 जिलों के लोगों ने अलग-अलग समूहों में बैठकर अपनी-अपनी कार्ययोजना बनाई। 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें वैद्यनाथ साहा का लोकगीत सुनकर सभी मित्रों का मन झूम गया। 8.30 बजे रात को भोजन हुआ और फिर विश्राम।

दूसरे दिन सुबह 9.00 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। सुनील कुमार मंडल ने संक्षेप में पहले दिन की कार्यवाही सबके सामने रखी। फिर विजय कुमार ने मिथिला जैसे नदियों के क्षेत्र, उनकी समस्याएं, उनके हल, सरकार की नीति और लोकविद्या आधारित प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार जल स्रोतों से भरा पड़ा है। बाढ़ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और प्राचीनकाल से बाढ़ के क्षेत्रों में सभ्यताएं विकसित होती रही हैं। बाढ़ समस्या का रूप ग्रहण करे इसके पीछे आज के समाज की प्रवृत्तियां हैं। बांध नदी के साथ आने वाली मिट्टी और गाद को बहने से रोकते हैं, नदी उथली होती जाती है और बांध के ऊपर के क्षेत्रों में पानी फैलता है। तटबन्ध के चलते भी पानी नये-नये इलाकों में फैलता है और विस्थापन को जन्म देता है। सरकार के तरकस में बांध ही बांध है और जनता की समस्या बढ़ती चली गई है। उत्तर बिहार से जितने लोगों को बाहर काम करने जाना पड़ता है वैसी स्थिति शायद किसी भी और क्षेत्र में नहीं है। उनका कहना रहा कि इन क्षेत्रों की समस्या का हल उन्हीं की विद्या में है। गांव-गांव घूमिये, लोगों से बात कीजिए तो आप पायेंगे कि लगभग सभी समस्या की जड़ से परिचित है और हल क्या हो सकता है यह भी जानते हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई बात नहीं सुनती। विजय कुमार ने कोसी नदी, उसके इतिहास और वर्तमान रूप पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाढ़, विस्थापन और बेरोजगारी का एक ही हल है—लोकविद्या की पुनर्प्रतिष्ठा। और, यही काम लोकविद्या जन आंदोलन के मार्फत वे यहां करने जा रहे हैं।

अंतिम सत्र में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल के समूहों ने अगले तीन महीने के अपने यहां लिए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रस्ताव सबके सामने रखा। यह बताया कि किन गांवों, प्रखण्डों में जायेंगे, कहां बैठकें करेंगे इत्यादि। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य रहेंगे :

- लोकविद्या कार्यकर्ता तैयार करना
- कार्यक्रमों के लिए एक ढांचा बनाना
- गांव स्तर पर संगठन बनाना
- किसान संगठन का निर्माण करना

इस सत्र में और लोगों ने भी अपनी-अपनी बात कही। दरभंगा के चन्द्रवीर यादव ने शिविरार्थी समूह की ओर से लोकविद्या जन आंदोलन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह तय हुआ कि दरभंगा में 31 मार्च से 1 अप्रैल, 2012 को एक लोकविद्या जन आंदोलन का अधिवेशन किया जायेगा।

•

ग्राम विद्यालोक किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं

दिलीप कुमार 'दिली', वाराणसी

पिछले तीन वर्षों से लोकविद्या अध्ययन पीठ के अंतर्गत वाराणसी के ग्राम सलारपुर, खालिसपुर, दीनापुर, नेवादा, संत रविदासनगर (भदोही) के हरिहरपुर, इलाहाबाद के बरनपुर व जौनपुर के पटैला गांव में सघन संपर्क करके तरह-तरह की विद्या से काम करने वाले जानकारों का अध्ययन करते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गांव में एक ही आदमी कई तरह के काम करने की जानकारी रखता है। घूरहू, कतवारू, दुक्खी ऐसे बहुतेरे मिले जो खेती, पशुपालन, बुनाई, जोड़ाई, नल-नाली की जानकारी से कोई न कोई काम करके रोजी-रोटी चलाते हैं। गांव के एक आदमी में इतने तरह का ज्ञान होते हुए भी काम लगने या मिलने का असमंजस रोज बना रहता है। चूंकि काम करना है इसलिए एक न मिला तो जो मिला उसी को करके विद्या ग्रहण कर लेता है। ताकि समय आने पर समाज की आवश्यकता का समाधान अपने ज्ञान, विद्या के मार्फत लोकहित के सेवार्थ प्रयोग कर सके। एक गांव समूचे तौर पर विश्वविद्यालय ही है जो लिखित में दी जाने वाली विद्या के बजाय कार्य रूप प्रदान कर रहा होता है। कई चीजें तो समाज की मांग के अनुसार भी रची जाती हैं। प्लास्टिक के समान को कई तरह से प्रयोग में लाने का प्रयास, कुम्हार का बर्तन, धरकार की दउरी, सन की सुतली के साथ-साथ नायलान व प्लास्टिक बोरी को उखाड़ कर सुतली, पावरलूम से कटी तानी की सुतली, चारपाई बुनाई का कारोबार गांव के नये बाजार का स्थान बनता है। प्लास्टिक मशीन, पावरलूम मशीन, कार-बस, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल के मिस्त्री व चालक, बिजली की तरह-तरह के कार्य करने वाले वाइण्डर, फीटर, टर्नर के विशेषज्ञ गांव से आते हैं। देखते-देखते पंचकोसी चौराहा से चन्द्रा तक का बाजार बहुत-सी शहरी आवश्यकताओं को पूरा कर ही देता है। यहां से सेवा कार्य करने वाले स्थानीय लोग हैं। कम्प्यूटर, मोबाइल को भी लोक उपयोग में प्रसारित करने के लिए भी लोग प्रयत्नशील हैं।

एक गांव के विद्यालोक में किसान, कारीगर, महिलाएं, छोटे दुकानदार, वनवासी पांच तरह के ज्ञानी बसते हैं। किसी गांव में इनमें से कोई कम अधिक होता है। ये गांव के विद्याधर हैं और इन्हें विश्वविद्यालय के विद्याधर के बराबर प्रतिष्ठा मिले, यही लोकविद्या आंदोलन है।

किसान : किसान खेत में अपने ज्ञान में लोगों की जानकारी फेंटकर अपनी विद्या को नया करता हुआ उत्पादन का कार्य करता है। विश्वविद्यालय में कृषि विभाग और कृषि प्रोफेसर के ज्ञान को खेती करने वाला किसान अपनी विद्या में ढालता है, इसका श्रेय भले ही प्रोफेसर उठा ले जाये लेकिन वास्तव में किसान अपनी जरूरत और स्थितियों के अनुसार उस ज्ञान को ढाल कर नवीन कर इस्तेमाल में लाता है। इस तरह वह किसान ज्ञान को संस्कारित कर उच्च ज्ञान को प्रसारित कर रहा है। अशिक्षित होते हुए कृत्रिम व प्राकृतिक आपदाओं को झेलकर तथा तमाम असुविधाओं को झेलते हुए, कई तरह की अन्य विद्याओं के सहयोग से अपनी विद्या व कौशल के आधार पर उत्पादन करता है। एक किसान अपनी खेती के लिए अनगिनत किस्म का जतन करता है। खाद, बीज, पानी, बिजली के गैर-बराबर बंटवारे के चलते हर कदम पर संघर्ष करने के लिए वह विवश होता है। उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने से किसान की कमर टूट जाती है। तीन बीघे खेत वाला किसान पचीस हजार रुपये लागत लगाकर बड़ी मुश्किल से तीस हजार रुपये कमा पाता है। इसमें उपज के साथ भूसे-डंठल का भी मूल्य शामिल है। जबकि कृषि विभाग का चपरासी वर्ष भर में दो लाख रुपये कमाता है। किसान विभिन्न तरह की विद्या का ज्ञानी है इसलिए उसे उसके ज्ञान के आधार पर कार्य करने का पक्का अवसर मिलना चाहिए। यदि किसान की आमदनी आज के हिसाब से 20,000 रुपये प्रति माह होगी तो ज्ञान, काम, उत्पादन, मांग और पूर्ति में चहुंमुखी सृजन होने लगेगा।

कारीगर : कारीगर अपनी कला हुनर के बूते जीविका चलाते हुए लोक-आवश्यकता के अनुकूल कार्य करता है। बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, दर्जी, मोची इत्यादि अपनी कारीगरी के साथ-साथ अन्य किस्म की कारीगरी का कार्य भी करते हुए देखे जाते हैं। जैसे राजगीरी, छोटी दुकानदारी, आटो, रिक्शा चलाक, साइकिल मिस्त्री, बढ़ईगीरी आदि कार्यों के साथ-साथ एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं। मशीनी साम्राज्य के बाजार को चुनौती देने वाला स्थानीय कारीगर ही होता है। कारीगर वर्षभर में बमुश्किल आय के नाम पर 25-50 हजार रुपये कमा पाता है। इस समय बिजली आश्रित कारीगरी में कार्य ज्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे पावरलूम, बिटाई, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, वेल्डिंग, लांड्री, सैलून, टी. वी.-फ्रीज मरम्मत, बाइंडिंग, कम्प्यूटर, मोबाइल इत्यादि क्षेत्र। बिजली का गैर-बराबर बंटवारा आर्थिक तंगी के आग में घी का काम करता है। यदि कारीगर को काम के समय बराबर बिजली मिले, रुचि का पक्का अवसर मिले और पक्की आमदनी यानि आज के हिसाब से 20,000 रुपये प्रति माह मिले तो कारीगर के कार्य को गति मिलेगी और लोकहित सधेगा। कारीगरों के हुनर के चमत्कार की शक्ति बहुत तेजी से चौतरफा बढ़ेगी।

महिला : गृह कार्य के अलावा समाज की आवश्यक मांगों को पूरा करने में सबसे ज्यादा ज्ञान महिलाएं लगाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान का प्रबंधन महिलाओं के ज्ञान-विद्या से ही संभव हो पाता है। कृषि में बीज संरक्षण, पशुपालन, ईंधन, तरह-तरह के व्यंजन, मसाले-बड़ी, आचार-मुरब्बा की जानकारी घर की महिलाओं के पास है। कपड़ा, क्षेत्र में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, साड़ी-टिक्की, जरदोजी-आरी इत्यादि कार्य करती हैं। इन सभी कामों की कोई कमी नहीं है। लेकिन महिलाओं के इन कामों के लिए पक्की आमदनी की कोई योजना सरकार नहीं बनाती और उन्हें बेगार के मजदूर बनाकर छोड़ देती है। लोकविद्या आंदोलन महिलाओं को घर बैठे पक्की आमदनी (यानी हर महीने पक्का वेतन) की व्यवस्था को बुलंद करता है। अर्थव्यवस्था में बदलाव की योजना सामने रखता है।

छोटे दुकानदार और आदिवासी समाज को भी पक्की आमदनी और वेतन की व्यवस्था होनी होगी तभी यह देश और समाज खुशहाल होगा।

•

किसान यूनियन के बढ़ते कदम

किसान यूनियन की पंचायतों में हमेशा दूरगामी उद्देश्यों और तात्कालिक प्रश्नों के बीच समन्वय का प्रयास रहता है। यूनियन के निर्माता एवं महान नेता चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत के निधन के बाद लोगों के मन में यह संदेह उभरा कि क्या अब यूनियन अपना संगठन और संतुलन बनाकर रख सकेगा? पिछले आठ महीने की गतिविधियों का यही संकेत है कि संतुलन बनाये रखने और आगे के लिए नजरिया विकसित करने की दृष्टि से अच्छे कदम उठाये गये हैं। विद्या आश्रम समूह इस किसान आंदोलन का खुला भागीदार है। इस दौर में हरिद्वार की महापंचायत, इलाहाबाद की महापंचायत, किसान आंदोलन के राष्ट्रीय समन्वय, वाराणसी मण्डल की संगठनात्मक समीक्षा और लोकविद्या के प्रथम अधिवेशन के दौरान यूनियन के शीर्ष नेताओं के साथ हमारी सघन वार्ता हुई है। यहां हम दो बातों का जिक्र करना चाहते हैं जो यूनियन के एजेण्डे पर नई उभरी हैं।

पहली बात यह है कि किसान को अपनी लागत और पैदावार दोनों कम करनी चाहिए। तीस साल का किसान आंदोलन का अपने संघर्षों का और सरकार से वार्ता का अनुभव यह बताता है कि लागत का दाम से कोई रिश्ता नहीं है बल्कि सरकार उत्पादन की मात्रा के हिसाब से दाम तय करती है। उत्पादन ज्यादा होता है तो दाम कम मिलते हैं, क्रय केन्द्र काम नहीं करते हैं। उत्पादन कम होता है तो दाम ज्यादा मिलते हैं। इसलिए किसान यूनियन लागत कम करने और उत्पादन कम करने के विषय पर विचार कर रहा है। यह एक नये संघर्ष का विचार है। और किसानों को 'फसल सत्याग्रह' की ओर ले जाता है। आन्ध्र प्रदेश में तटवर्ती इलाकों में धान के खेत परती छोड़कर अपना जज्बा सबके सामने लाया है। वर्तमान चुनावों में भागीदारी न करके यह भी रेखांकित किया है कि किसान की खुशहाली का रास्ता संघर्षों से ही निखारा जा सकता है।

दूसरी बात किसान परिवारों की नियमित और पक्की आय से सम्बन्धित है। वे परिवार ही खुशहाल नजर आते हैं जिनके यहां कम से कम एक पक्की नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है। यही वे परिवार भी हैं जो व्यवस्थित किसानी कर पाते हैं और कृषि को अपनी खुशहाली का एक स्रोत बना पाते हैं। लोकविद्या जन आंदोलन के वाराणसी अधिवेशन में हर परिवार में एक पक्की नौकरी की बात उठायी गयी थी। यह बात उठायी गयी थी कि ग्रामीण समाज का हर व्यक्ति और हर परिवार अपने ज्ञान के बल पर अपनी जीविका चलाने की क्षमता रखता है। इसलिए लोकविद्या के आधार पर सबको नियमित आय की व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने इस मांग का खुला समर्थन किया है। वाराणसी मण्डल की पंचायत ने इस मांग पर संगठन को एकजुट करने का कार्यक्रम बनाया है।

किसान यूनियन इस देश का सबसे बड़ा जन संगठन है। उन लोगों का जन संगठन है जिनकी खुशहाली से पूरे देश की खुशहाली बनती है। आशा है कि किसान आंदोलन के कदम इन रास्तों पर आगे बढ़ते रहेंगे।

•

चुनाव का विकल्प कहां है?

अभी हाल में कई राज्यों में चुनाव हुए। अधिकांश किस्म के सामाजिक कार्यकर्ताओं और उनके संगठनों ने इन चुनावों में भाग लिया। छोटे-छोटे अपने को प्रगतिशील कहने वाले संगठन हैं, वामपंथी के नाम पर पहचाने जाने वाले स्थानीय संगठन एवं कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के रूप में पहचाने जाने वाले संगठन हैं, अपने को गांधीवादी कहने वाले संगठन हैं, जन आंदोलनों के समन्वय वाले मोर्चे हैं, सभी ने चुनाव में भाग लिया। कुछ ने अकेले भाग लिया, कुछ ने गठबंधन बनाकर शिरकत की। भाग लिया मतलब अपने उम्मीदवार खड़े किये और साझा उम्मीदवारों के लिए काम किया। अधिकांश गांधी या मार्क्स की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपना मौलिक वैचारिक नेता मानते हैं। ये सारे वे संगठन हैं जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह बनाने में ये चुनाव कैसे मदद करेंगे, यह देखने में हम असमर्थ हैं। उल्टे हमें तो लगता है कि इन सब लोगों की भागीदारी से अभी की व्यवस्था को मिलने वाली मान्यता पक्की होती है।

इनमें अधिकांश लोग वे हैं जिन्हें समाज के साथ सरोकार होता है, जो ईमानदारी और सादगी से अपनी जिन्दगी जीते हैं और अपने आसपास होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं और संघर्ष करते हैं। इनकी जिन्दगी में आपको त्याग दिखाई देगा, कर्मठता और विचार का संगम दिखाई देगा। ये समाज के नगीने हैं। लेकिन क्या विडम्बना है कि इस महाभ्रष्ट और शोषणकारी व्यवस्था को मान्यता दिलवाने वाली और चलाने वाली चुनाव रूपी मुकुट में ये नगीने जड़े दिखाई देते हैं। इससे तो केवल यह मुकुट ही और सुन्दर हो रहा है।

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में यह सवाल उठा कि किसी व्यवस्था को लागू करने का अन्तिम निर्णय किसके हाथ में हो। जब संसद ने अपना अंतिम अधिकार जताया तो तमाम लोगों ने यह कहा कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ होता है, समाज के पास यह हक होता है लेकिन यदि समाज का प्रतिनिधित्व करने की इजारेदारी संसद और विधानसभा के पास हो तो समाज के इस हक की बात बेमानी हो जाती है और वास्तविक हकदार चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था ही बन जाती है। लेकिन जब यह सवाल उठ चुका हो तब हम समाज के प्रतिनिधित्व और रास्ते खोजने की जगह संसद और विधानसभाओं के चुनावों में शामिल हो जाते हैं तो हमारा यह कदम यह मानने के बराबर हो जाता है कि जनता के प्रतिनिधित्व की संस्थाएं वही हो सकती हैं। जो लोग लोकतंत्र को एक मूल्य समझते हैं और उसे अपने जीवन और गतिविधियों में अंगीकार करते हैं, क्या वे लोकतंत्र की एक व्यवस्था और लोकतंत्र के मूल्य में अंतर केवल वैचारिक बहसों तक ही सीमित कर देते हैं? और वास्तविक जीवन में एक सर्वथा नाकारा व्यवस्था की मान्यता ही बढ़े ऐसे कदम उठाने को अपने को मजबूर पाते हैं? यह तो अद्भुत हताशा का प्रतीक है। खेत में खोई अंगूठी को रास्ते पर बिजली के खम्भे की रोशनी में खोजा जा रहा है। शायद वे भी ये सब जानते हैं। फिर इस मजबूरी से निकलने का रास्ता क्या है?

एक ही रास्ता है—जनता के पास वापस जाने का और लोकविद्या के सहारे अपने राजनैतिक विचारों को फिर से गढ़ने का। जैसे सामान्य जीवन सबसे उच्चकोटि का जीवन होता है, आम लोगों की भाषा यानि सामान्य भाषा में भाषा जगत की सही-गलत की कसौटी होती है वैसे ही लोकविद्या वह खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र के तरकश खाली हो चुके हैं। लोकविद्या के शरण जाने का कोई विकल्प नहीं है। लोकविद्या और लोकविद्याधर समाज की एकता इन्हीं के पास जाना 'बुद्धं शरणम् गच्छामि' और 'संघम् शरणम् गच्छामि' के वर्तमान रूप हैं। इसी से आज का 'धम्म' तैयार होगा यानि बदलाव की राजनीति तैयार होगी।

•

ये कैसी मजबूरी?

तीन साल का अभिज्ञान और एक साल की एश्वर्या, ये दोनों उस जवान बंगाली दम्पति के बच्चे हैं जिन्हें नार्वे के प्रशासन ने उनके माता-पिता से अलग करके अपने पास रख लिया है। अब नौ महीनों से ये बच्चे अपने मां-बाप से अलग नार्वे की प्रशासन की देखरेख में हैं। मीडिया में बड़ा हंगामा है। अखबार और टेलीविजन शुरू से लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं और एक तरह से बच्चे वापस मां-बाप को मिले, इसके लिए अभियान चला रहे हैं पर नतीजा अभी तक सिफर ही है। भारत सरकार बच्चे वापस प्राप्त करने में असफल रही है। शासन को अपनी किसी असफलता पर शर्म भी आती हो इस पर से तो अब काफी समय से लोगों का विश्वास तो उठ ही चुका है। अब 23 मार्च को नार्वे की स्थानीय अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। नार्वे का एक जिला जज इस पर फैसला देगा। वे कहते हैं कि उनके यहां यही व्यवस्था है। भारत सरकार मजबूर है। ये बच्चे इस आरोप के साथ उठा लिये गये थे कि जैसी देखभाल उनकी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही थी। नार्वे प्रशासन को इस बात पर आपत्ति थी कि मां बच्चों को अपने पास सुलाती थी और हाथ से खाना खिलाती थी।

नार्वे यूरोप के एकदम उत्तरी भाग में स्थित लगभग चार लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का देश है। इसकी आबादी 50 लाख की है। आज की तारीख में यह दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में है। इसकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दुनिया में सबसे अधिक है। यानि जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के विनाश में इसका प्रति व्यक्ति योगदान सबसे अधिक है। लम्बे समय तक यह कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता रहा है। जाहिर है कि औपनिवेशिक काल से तीसरी दुनिया की लूट का भरपूर हिस्सा वहां लगा हुआ है। अब यह देश तहजीब सिखा रहा है। बच्चों पर अत्याचार की इस घटना ने उधर के यूरोपीय समाज को बेनकाब कर दिया है। हमारी कहानियों में राक्षसों की शक्ल सफेद होनी चाहिए।

हमारी समस्या उनके मूल्यों को श्रेष्ठ समझने की है। अकेले-अकेले रहने को और समुदाय का अनादर करने को हम प्रगति का द्योतक मानते हैं। इसीलिए हम बच्चों को नहीं छुड़वा पा रहे हैं। हमें खुलेआम यह कहना चाहिए कि हमारे मूल्य अलग हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समन्वय का रास्ता अपनाना होगा। वर्तमान प्रश्न जैसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय कानून के तहत अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। इतने गंभीर प्रश्न पर भारत सरकार की असफलता, ताकत, नजरिया, कूटनीति, राजनीति हर दृष्टि से उसके अद्भुत खोखलेपन और गैर-जिम्मेदार व्यवहार को उजागर करती है। हमारा अपना संकट जितना गहरा हम समझते हैं, उससे कहीं अधिक गहरा है।

•

लोकविद्या जन आंदोलन

लोकविद्या ताना-बाना का विचार

सूचना युग में ज्ञान की दुनिया में अस्थिरता का एक बड़ा दौर शुरू हुआ है। नये दावे, नई कसौटियां, गतिविधियों के नये स्थान, नये किस्म की गतिविधियां और औजार अस्तित्व में आये हैं और ज्ञान की दुनिया की पूरी संरचना ही डांवाडोल हो गई है। ज्ञान को साइंस की जकड़न से मुक्त करने की संभावनाएं पैदा हुई हैं। एक तरफ ज्ञान के दर्शन में बड़े वैचारिक घमासान की शुरुआत हुई है, जिसमें लोकविद्या के दावे के लिए सम्मानजनक और मान्यता प्राप्त मौके पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ ज्ञान के प्रबन्धन तथा सोशल मीडिया ने विकास और राजनीति की नई चौखटें पैदा करनी शुरू कर दी हैं जिनके चलते लोकविद्या विचार से प्रेरित सामाजिक संरचनाओं की कल्पना और लोकविद्या आधारित संचार-संपर्क के जरिये बदलाव की राजनीति बनाने के मौके पैदा हुए हैं। लोकविद्या जन आंदोलन और लोकविद्या ताना-बाना इन्हीं ये मौकों में लोकविद्याधर समाज की पहल को आकार देने के उपक्रम हैं।

वाराणसी में नवम्बर 2011 में लोकविद्या जन आंदोलन के प्रथम अधिवेशन में यह उभर कर आया कि :

1. लोकविद्या जन आंदोलन लोकविद्याधर समाज का ज्ञान आंदोलन है।
2. यह समाज के सामने लोकविद्या का व्यापक और दूरगामी दावा पेश करता है।
3. यह लोकविद्याधर समाज के विभिन्न अंगों के आंदोलनों के प्रति लोकविद्या दृष्टिकोण विकसित करता है।
4. यह लोकविद्याधर समाज के विभिन्न अंगों के आंदोलनों में लोकविद्या दृष्टिकोण शामिल करने की विविध पहल को आकार देता है।
5. यह छोटी एवं स्थानीय संस्थाओं, संगठनों, संघर्षों तथा प्रकाशनों व अन्य सम्पर्क संचार उपक्रमों के साथ भागीदारी एवं सक्रिय सम्बन्धों के जरिये कार्यकर्ता की दुनिया में लोकविद्या विचार का प्रचार-प्रसार करता है।
6. यह लोकविद्याधर समाज में एकता के व्यापक उद्देश्यों के अंतर्गत अपने सभी कार्यों को आकार देता है। इसी में यह लोकविद्या दृष्टिकोण की कसौटी भी देखता है।
7. संसार के सामने लोकविद्या का दावा पेश करने तथा लोकविद्याधर समाज में एकता स्थापित करने के लिए संचार, सम्पर्क और आपस में सम्बन्ध बनाने की नई प्रक्रियाओं और वैसे ढांचे की जरूरत है। *लोकविद्या ताना-बाना* इसी की एक कल्पना है।

लोकविद्या जन आंदोलन को सम्पर्क और संचार के एक ऐसे ढांचे की जरूरत है जो लोकविद्याधर समाज के लिए मीडिया जैसा काम करता हो। नवम्बर 2011 के वाराणसी के अधिवेशन में वैकल्पिक मीडिया अथवा लोकविद्या मीडिया के नाम से इस तरह की बातें की गई थीं। उसके बाद से आपसी चर्चाओं में यह बात उभर कर आती रही कि 'मीडिया' शब्द का प्रयोग उन भावों, तस्वीरों, परम्पराओं और रुझानों को जागृत करना है जो लोकविद्याधर समाज के हित में नहीं रहे हैं तथा इससे नये लोकविद्या प्रेरित विचारों को आकार लेने में बाधायें पैदा होती हैं। इन्हीं चर्चाओं में 'ताना-बाना' शब्द रचना उभर कर आई। यानि यह कि जो बातें हम लोकविद्या जन आंदोलन के संदर्भ में 'वैकल्पिक मीडिया' अथवा 'लोकविद्या मीडिया' से कहने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं बातों को संगठित तौर पर आगे ले जाने के लिए 'लोकविद्या ताना-बाना' का प्रयोग किया जाये। इसी में इस शब्द रचना के सही और उपयुक्त होने का परीक्षण भी होगा। यह लोकविद्या जन आंदोलन का संपर्क-संचार का माध्यम, तरीका अथवा संगठन होगा।

1. जिस तरह लोकविद्या समाज का ही एक अंग होती है, किन्हीं संस्थाओं अथवा उपकरणों में नहीं बसती, उसी तरह लोकविद्या ताना-बाना के नाम से जिस संगठनात्मक स्वरूप की कल्पना की जा रही है वह समाज में ही बसता है, समाज का ही एक अंग होता है।
2. लोकविद्या ताना-बाना उन सभी लोगों का संगठन है जो पहल लेकर लोकविद्याधर समाज के अंदर तथा उसकी रुचि एवं दृष्टि के अनुरूप लोगों के बीच सम्बन्ध व सम्पर्क विकसित करते हैं तथा लोकविद्या जन आंदोलन का संदेश वृहत् समाज में ले जाते हैं।
3. लोकविद्या ताना-बाना आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और दार्शनिक आदि को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखता, बल्कि उन्हें मानवीय क्रिया के आपस में अंतरंग विभिन्न पहलुओं के रूप में देखता है।
4. लोकविद्या ताना-बाना लोकविद्याधर समाज की क्रियाओं एवं अभिव्यक्तियों के बीच सम्पर्क स्थापित करके तथा नये सम्बन्धों के निर्माण के जरिये लोकविद्याधर समाज को उसकी खोई हुई दुनिया को प्राप्त करने और उसका पुनर्निर्माण करने का रास्ता बनाता है।
5. लोकविद्या ताना-बाना बनाने के लिए हमें अंग्रेजी शिक्षित समाज के 'प्रतिनिधित्व' के विचार की सीमाओं और खराबियों को समझना होगा। 'प्रतिनिधि' में समाज से अलग और ऊपर अस्तित्व की सत्ता है। समाज का कितना भी नैतिक, जिम्मेदार अथवा गुणी सेवक होना प्रतिनिधि को समाज के अंदर वापस नहीं लाता। उसका अस्तित्व ही समाज के बाहर की सत्ता की मूल मान्यता पर आधारित है। इसके चलते समय और स्थान के अनुरूप अलग-अलग ढंग से समाज का अधोगति को प्राप्त होना तय हो जाता है।
6. लोकविद्याधर समाज को प्रतिनिधि नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने ही समाज के ऐसे अंग विकसित करने होंगे जो वृहत् समाज में दखल लेकर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। लोकविद्या ताना-बाना एक ऐसे ही अंग को विकसित करने का प्रयास है।

2012 के दौरान लोकविद्या जन आंदोलन के सम्मेलनों, प्रकाशनों और परिचर्चाओं में लोकविद्या ताना-बाना के विचार पर खुली बहस चलनी चाहिए।

•

लोकविद्या ताना-बाना

लोकविद्या मीडिया पर दो दिवसीय चिन्तन परिचर्चा

19-20 फरवरी, 2012 : विद्या आश्रम, सारनाथ, वाराणसी

लोकविद्या ताना-बाना का यह शिविर विद्या आश्रम के कार्यकर्ताओं में मीडिया के सवाल पर सघन वार्ता का नतीजा था। 'वैकल्पिक मीडिया' अथवा 'लोकविद्या मीडिया' के नाम पर चलती रही इस चर्चा में लगातार यह महसूस किया जाता रहा कि मीडिया शब्द का प्रयोग भारी पड़ता है और जिन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और बौद्धिक संदर्भों से हम मुक्त होना चाहते हैं उनका ही संदर्भ चाहे-अनचाहे बनता रहता है। इन संदर्भों और मूल्यों को हटायें तो संचार, सम्पर्क, सम्प्रेषण, सूचना, सम्बन्ध इत्यादि बातें बची रह जाती हैं। तो बातचीत के दौरान यह विचार आया कि हमारे पास इस सबको समेटने वाला एक बढ़िया शब्द है—'ताना-बाना'। इसमें 'लोकविद्या' शब्द जोड़ा जाय तो दृष्टिकोण और समाज दोनों शामिल होता है। इस तरह 'लोकविद्या ताना-बाना' इस शब्द रचना का सृजन हुआ। तब यह विचार किया गया कि एक छोटी-सी गोष्ठी का आयोजन हो जिसमें वाराणसी के नजदीक के विद्या आश्रम के कार्यकर्ता और हम जिन्हें बुला सकते हैं ऐसे मीडिया की समझ रखने वाले और उसमें काम करने वाले प्रबुद्धजन शामिल हों और लोकविद्या ताना-बाना का विचार बनाने की सक्षम शुरुआत की जाय। नतीजे स्वरूप 19-20 फरवरी को आश्रम परिसर पर इस वार्ता का आयोजन हुआ।

शामिल लोग कुछ इस प्रकार थे—लोकविद्या जन आंदोलन दरभंगा से विजय कुमार, सुनील कुमार मण्डल और रामचरित पण्डित; सिंगरौली से अवधेश कुमार और अजय; वाराणसी से दिलीप, लक्ष्मण प्रसाद, एहसान अली, मोहम्मद अहमद, प्रवाल सिंह, नंदलाल, आरती, चित्रा सहस्रबुद्धे, बबलू कुमार और सुनील सहस्रबुद्धे; सोनभद्र से गुंजन सिंह; लखनऊ से रविशेखर और एकता सिंह; गया से रवीन्द्र पाठक और प्रमिला पाठक। मीडिया के विचारकों और रचनाधर्मियों में दिल्ली से के. पी. मधु और गीता मधु; पूर्णिया से राजेन्द्र पाठक और चन्द्रशेखर मिश्र; जयपुर से अविनाश मौर्य; पुणे से आनन्द सिंह तथा चेन्नई से सशिकांत। दिल्ली से केन्द्र सरकार के प्रकाशन विभाग से राजेश कुमार झा व रूबी झा और दिल्ली से ही इतिहासविद् व सामाजिक कार्यकर्ता वागीश कुमार झा।

चूंकि कई व्यक्ति लोकविद्या के विचार से तथा लोकविद्या जन आंदोलन के विचार से भी अच्छी तरह परिचित नहीं थे, इन पर बैठक के सामने विद्या आश्रम की ओर से एक व्यवस्थित विचार रखने का प्रयास किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि मोटे तौर पर किसानों, कारीगरों, छोटे-छोटे दुकानदारों, आदिवासियों और महिलाओं से जो समाज बनता है वह लोकविद्याधर समाज है। और यह कि इस समाज के उत्थान के रास्ते उन्हीं के ज्ञान और शक्ति से खुलते हैं। लोकविद्या ताना-बाना की भूमिका इसी संदर्भ में देखी जाये। लोकविद्याधर समाज की मुक्ति की अवधारणाओं, इस समाज की एकता और लोकविद्या की प्रतिष्ठा के बिन्दुओं के इर्द-गिर्द विचार प्रस्तुत हुए। खासकर लोकविद्या के आधार पर सबको पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, इसे

इस समाज की खुशहाली के प्रस्थान बिन्दु के रूप में सामने रखा गया। इन सभी बातों पर और इनसे पैदा होने वाले प्रश्नों पर तीखी चर्चा हुई। संगठित विद्या की वैचारिक चौखट और यूरोपीय प्रक्रियाओं से जन्में समीक्षात्मक दर्शन की सामाजिक भूमिकाओं पर भी तीखी चर्चाएं हुईं। पढ़े-लिखे लोगों में लोकविद्या की प्रस्तुति जब बदलाव के राजनैतिक दर्शन के स्रोत और आधार के रूप में होती है तो तीखी चर्चाओं का जन्म हमेशा ही होता है। चूंकि वार्ता में शामिल लगभग सभी लोग अक्सर उच्च शिक्षा की पृष्ठभूमि से आते हैं, लोकविद्या में आस्था के बावजूद उनके आंतरिक द्वंद्व प्रकट बहस का रूप ले लेते हैं। किसने क्या कहा यह महत्त्वपूर्ण न रहकर क्या बात हुई यही महत्त्व का और सीख लेने का स्थान बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न रूपों में और विभिन्न विषयों पर संगठित विद्या और लोकविद्या के मूल्यों और वैचारिक चौखटों के बीच टकराहट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्वविद्यालय के आपसी वार्ता के मूल्यों और आंदोलन में वार्ता के मूल्यों के बीच टकराहट हो जाती है। इस टकराहट में नये सृजन का महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। लोकविद्या ताना-बाना के लिए आयोजित इस वार्ता में हुई सैद्धांतिक चर्चाओं का लाभ आगे के काम में अवश्य मिलेगा।

जिन ठोस विषयों पर वार्ता हुई वे हैं—लोकविद्याधर समाज में आपसी सम्पर्क व सम्बन्ध की विधायें, नई तकनीकों का लोकविद्या ताना-बाना में प्रयोग, स्थानीय प्रयासों, सामुदायिक रेडियो का इस्तेमाल, संघर्षों को जोड़ने में लोकविद्या ताना-बाना की भूमिका और लोकविद्या ताना-बाना का समाज में स्थान—ठोस रूप में यह कितना लोकविद्या समाज का अंग होगा और कितना प्रतिनिधि।

लोकविद्याधर समाज में सम्पर्क स्थापित करने और सम्बन्ध बनाने के तरीकों और व्यवस्थाओं को जानने और समझने पर विशेष जोर दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि इस प्रक्रिया में उसी समाज के सदस्यों की भूमिका बहुलता में होना जरूरी है। समाज की भाषा और समझने के तरीकों को केन्द्र में रखना जरूरी है। यह हर क्षेत्र—सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि सभी को लागू होता है। नई तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य दिखाई देता है तथापि समाज द्वारा उन्हें आत्मसात् करने की आवश्यकता को नजरअन्दाज करने के उद्देश्य से ही भटकने की सम्भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नौजवानों की प्रवृत्तियों और समाज की दूरगामी जरूरतों के बीच सामंजस्य बनाना एक अति महत्त्वपूर्ण मूल्य के रूप में आकार लेना चाहिए। मोबाइल, सामुदायिक रेडिया और कम्प्यूटर के बारे में एक साथ विचार न करके प्रत्येक पर अलग-अलग समझ बनाना जरूरी है। नई तकनीकों का इस्तेमाल अक्सर साथ में उन तथ्यों व जानकारियों को भी इकट्ठा करता है जो पूंजी आधारित उद्योगों द्वारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए आंकड़ों और सूचनाओं के संग्रह गहरे संदेह को भी जन्म देते हैं। सामुदायिक रेडियो के इस्तेमाल पर लगाई गई तमाम सरकारी पाबन्दियों पर बात हुई। यह कहा गया कि इन पाबन्दियों से हताश होने की जगह छोटे-छोटे प्रयासों को आकार देना जरूरी है। लोकविद्या जन आंदोलन की दृष्टि से छोटे-छोटे स्थानीय प्रकाशनों को बढ़ाते हुए उनको आपस में जोड़ने की विधायें एवं व्यवस्थाएं विकसित करने की बात हुई। यह बात भी हुई कि लोकविद्या ताना-बाना को यदि लोकविद्याधर समाज की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में देखा गया तो इस ताना-बाना को उस समाज के बाहर और उसके नियंत्रणों से स्वतंत्र अस्तित्व को सैद्धांतिक मान्यता मिलती है और यह किसी भी दूरगामी दृष्टि से मान्य नहीं हो सकता। अतः लोकविद्या ताना-बाना को लोकविद्याधर समाज के एक अंग के रूप में समझना और बनाना जरूरी है। एक प्रस्ताव भी आया कि इस ताना-बाना में एक 'लोकविद्या प्रवक्ता' की कल्पना की जा सकती है। लोकविद्या प्रवक्ता लोकविद्याधर समाज का ही व्यक्ति होगा और शायद लोकविद्या ताना-बाना की मूल इकाई भी। इसपर तेज बहस हुई, अनेक संदेह व्यक्त किये गये और प्रश्न उठा कि इस पूरी प्रक्रिया में पढ़े-लिखे लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? चूंकि वे लोकविद्याधर समाज के अंग नहीं हैं। अंग वे हैं नहीं, प्रतिनिधि के विचार में मौलिक समस्या है तो वे क्या हो सकते हैं? 'सेवक' और 'साथी' जैसे शब्दों का प्रयोग लम्बे समय से उन आंदोलनों में होता रहा है जिन्होंने लोकविद्याधर समाज को आंदोलित किया है। कुछ ऐसी ही बातों के साथ इस वैचारिक घमासान की शुरुआत हुई है और आशा है कि लोकविद्या ताना-बाना का विचार विकसित करने और समाज में उसे बनाने के कदमों को इस दो दिवसीय वार्ता से स्पष्टता मिली है और बल भी।

गोष्ठी के अंत में लोकविद्या ताना-बाना के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें रवि शेखर (संयोजक), एकता, गुंजन, दिलीप कुमार 'दिली', अजय और सुनील कुमार मण्डल शामिल हैं।

•

लोकविद्या मीडिया शिविर

एकता, लखनऊ

19 फरवरी 2012 की दोपहर विद्या आश्रम परिसर पर सारनाथ के आसपास के गांवों के युवा साथियों के लिए एक लोकविद्या मीडिया शिविर का आयोजन किया गया। 15 युवक और 2 युवतियां इस शिविर में शामिल हुए। इनमें से अधिकांश सारनाथ के पास के गांवों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे संघर्षों में भाग लेते हैं। शिविर के शुरू में लोकविद्या विचार, लोकविद्याधर समाज तथा इस समाज की स्थितियों व संघर्षों के बारे में बताया गया।

इस शिविर के उद्देश्यों का परिचय देते हुए विद्या आश्रम के सदस्य बबलू कुमार ने कहा कि समकालीन अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं के पक्षपातपूर्ण रवैये को देखते हुए संघर्ष के साथियों का मीडिया के क्षेत्र में दखल देना जरूर है। दिलीप भाई, रवि शेखर, एकता, गुंजन, लक्ष्मण प्रसाद ने इस शिविर के संदर्भ में अपने विचार साझा करते हुए मुख्यतः इस बात पर बल दिया कि संघर्ष के साथियों द्वारा उन बिन्दुओं की पहचान करना जरूरी है, जिनके माध्यम से वे मुख्य धारा के समाचार-पत्रों की एकतरफा और पक्षपातपूर्ण खबरों से हो रहे दुष्प्रचार के खिलाफ कदम उठा सकते हैं।

इस शिविर में आये साथियों के साथ रवि शेखर, एकता, आनंद, अविनाश और गुंजन ने मोबाइल और कैमरे का उपयोग मीडिया के औजारों के रूप में किये जाने के संदर्भ में अपनी जानकारियां साझा कीं। सभी शिविरार्थियों को निम्न जानकारियां दी गयीं और साथ ही उनसे अभ्यास भी कराया गया।

- मोबाइल फोन से तस्वीर खींचना और वीडियो बनाना,
- मोबाइल फोन से एक व्यक्ति को या समूह को संदेश भेजना
- मोबाइल फोन में बातचीत को टेप करना
- कैमरे से तस्वीर खींचना और वीडियो बनाना
- मोबाइल फोन में उपलब्ध ब्लूटूथ का उपयोग
- मोबाइल फोन और कैमरे में मौजूद फाइलों का कम्प्यूटर में स्थानान्तरण

- कम्प्यूटर में स्थानांतरित फाइलों को उचित स्थानों पर सुरक्षित करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें देखना, दिखाना।

अभ्यास सत्र के पूर्व चित्रा जी ने इस शिविर के आयोजन के प्रेरणास्रोत ककरहिया गांव के ब्रजेश कुमार के बारे में बताते हुए कहा कि जब बरईपुर गांव में संघर्ष अपने चरम पर था तो पुलिस और प्रशासन को गांव के बाहर खदेड़े जाने और सभी गांव वालों की एकजुटता की खबर जहां किसी अखबार ने नहीं छापी ऐसे में ब्रजेश ने उस दिन के संघर्ष का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया, यह न केवल एक साहसिक काम है बल्कि समझदारी भरा भी है। उसके द्वारा ऐसा किये जाने और बाद में वह वीडियो दूसरे लोगों से साझा किये जाने से ही इस शिविर की योजना बन पायी और यह महसूस किया गया कि उपलब्ध तकनीक का उपयोग समझ लेने पर संघर्ष के स्थान पर मौजूद सभी व्यक्ति मिलकर स्वयं ही मीडिया की भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से ही लोकविद्या ताना-बाना बनना है।

•

हे द्रौपदी, सुनो!

चेन्नई के पश्चिम के अर्काट जिले के कई गांवों में महाभारत का एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के लगभग 300 गांवों में यह उत्सव आज भी मनाया जाता है। यह त्यौहार 20 दिन चलता है। रोज 20 घंटे कार्यक्रम होते हैं। सुबह कर्मकाण्ड होता है, दोपहर को कथा सुनाई और सुनी जाती है और रातभर लीला होती है यानि नाट्य मंचन समारोह होता है। यह उत्सव द्रौपदी के इर्द-गिर्द चलता है। महाभारत का यह कथानक कई अर्थों में जिस महाभारत से हम सब परिचित हैं उससे अलग है। यह उस क्षेत्र के इतिहास से सराबोर है। इसमें छठी सदी तक की स्मृति समाविष्ट है और बाद के घटनाक्रमों का भी समावेश होता चला गया है। यह महाभारत शांति का संदेश लेकर आता है। यह एक युद्ध विरोधी मानव भाव का उत्सव है। यह उस क्षेत्र में हुए युद्धों में जो नुकसान हुए उनको नहीं संजोता है बल्कि लोगों की प्रतिरोध शक्ति और लचीलेपन का समारोह है। द्रौपदी जनता के इस भाव और दृष्टिकोण की प्रतिनिधि प्रतीक है। उसकी पूजा लोग एक देवी के रूप में करते हैं।

छठी सदी में पल्लव राजाओं और चालुक्य राजाओं के बीच शुरू हुए युद्धों से शायद इस क्षेत्र में इतिहास का एक नया काल शुरू होता है। महाबलिपुरम् का मूर्ति शिल्प इन्हीं युद्धों की याद्दाश्त से जुड़ा बताया जाता है। कहा जाता है कि उसी के बाद किसी समय महाभारत ने उस क्षेत्र में एक व्यापक जनहितकारी लोकनाट्य समारोह का रूप लिया जो युद्ध विरोधी था और लोकशक्ति के लचीले रूप को सामने लाता रहा। यह नाट्य परम्परा उस क्षेत्र की एक महान वास्तविकता का संदर्भ लेती है। वहां ऐसा होता था कि जब कोई भी राजा युद्ध करता हुआ और जीतता हुआ आता था तो उसे गांव वालों से गांव की सीमा के बाहर वार्ता करनी पड़ती थी। यह वार्ता उस समझौते के लिए होती थी जिसके अंतर्गत राजा और उसकी व्यवस्था का गांव में प्रवेश वर्जित होता था तथा यह मानने के लिए राजा गांव के सामने अपनी मांग रखता था जो सामान्य तौर पर कर के रूप में होती थी। इस समझौते में

... शेष पृष्ठ 6 पर

पृष्ठ 5 का शेष

गांव अपनी व्यवस्थाओं की स्वायत्तता बरकरार रखता था तथा उसके एवज में उसकी कीमत चुकाता था। गांव के बाहर के पत्थर के प्रतीक ऐसे ही घटनाक्रमों की वास्तविकता उजागर करते हैं। द्रौपदी इस प्रक्रिया में गांव का नेतृत्व करती है। वह आगंतुक राजाओं, जिनमें मुसलमान राजा शामिल हैं, उनके साथ वार्ता करती है। इसी के इर्द-गिर्द कर्मकाण्ड, कथा-वाचन और नाट्य संयोजन का यह महाभारत एक महान ऐतिहासिक रूपक बन जाता है।

अंग्रेजों के आने के समय तमिल देश में छोटे-छोटे राजाओं की व्यवस्था है। उन्हें किलेदार (पालीगार) कहा गया है। इन राजाओं ने अंग्रेजों से लम्बे समय तक लड़ाइयां लड़ीं। इन सबको हराकर अंततः अंग्रेजी राज 1810 के आसपास कायम हो गया। महाभारत की उपरोक्त परम्परा कमोबेश अपने संदेश और विकासशील कथानक के साथ इस वक्त तक चलती रही। अंग्रेजी राज के समय कथानक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जनता का स्थान पराक्रमी राजाओं और योद्धाओं ने ले लिया। युद्धों में उनका खेत आना बलिदान के रूप में समझा जाने लगा और महाभारत एक दुखांत समारोह बन गया। द्रौपदी गायब हो गयी। पहले द्रौपदी के महाभारत में जनता क्रियाशील थी और अंतिम नतीजा शांति का होता था। जबकि अब महाभारत योद्धाओं के बलिदान या शहादत का हो गया, द्रौपदी की भूमिका नहीं रह गयी और शोषण व अत्याचार की बातों को स्थान मिलने लगा।

अभी तक जो समारोह गांवों में होता है वह उस इलाके का एक अद्वितीय उत्सव होता है। सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं। खाना, कपड़ा, समारोह, स्थल, मंचन, कर्मकाण्ड, कथावाचन इत्यादि अनेक काम होते हैं जिनकी जिम्मेदारी अलग-अलग जातियों के लोग उठाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में हर वर्ष का क्रम कई जगह टूटा है किन्तु वहां के युवाओं में, जो काम करने बाहर निकल गये हैं उनमें भी, इसके प्रति बड़ा आकर्षण है और वे सब ये कहते हैं कि हम इसे जारी रखेंगे।

*(सशिकांत तमिलनाडु के एक फिल्म निर्माता हैं। छोटी-छोटी फिल्में बनाते हैं। उन्होंने 'सुनो द्रौपदी' नाम से इस समारोह को चित्रित करने वाली एक-दो घंटे की फिल्म बनायी है। यह फिल्म विद्या आश्रम में 21 फरवरी, 2012 को सशिकांत की उपस्थिति में दिखायी गयी। इस फिल्म को देखना एक उच्चकोटि का विलक्षण अनुभव रहा। फिल्म बेहद सुंदर है। घटनाक्रमों और जन-भागीदारी का अद्‌भुत समायोजन प्रस्तुत करती है। ऐसी कला और भाव-प्रदर्शन का लोक पहल पुनर्निर्मित करने में बड़ा योगदान हो सकता है। सशिकांत लोकविद्या ताना-बाना की ज्ञान वार्ता और शिविर में भाग लेने के लिए चेन्नई से वाराणसी आये थे। उन्होंने वार्ता के दौरान जो कहा और फिल्म देखकर हमें जो समझ में आया उसके आधार पर हमने यह लिखा है। –**सम्पादक**)*

•

लोकस्मृति और इतिहास

लोकविद्या में इतिहास और इतिहास की चेतना लोकस्मृति का रूप लेती है। लोकस्मृति कोई ऐसा स्थिर कथानक नहीं होती जो भूत की घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित करके स्थिर कर दे, जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बल्कि लोकस्मृति रस्मों, कहानियों और कलाओं में संजोई और अभिव्यक्त होती है। यह परिवर्तनशील है, इसके चलते लोकविद्या में भूत और भविष्य दोनों खुले और परिवर्तनशील होते हैं। और इससे जुड़े चेतना के रूप में मनुष्य की गतिविधि और पहल के लिए विविध विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जबकि इतिहास और आधुनिक ज्ञान के प्रकार भूत को, 'जो हो चुका है और अब बदला नहीं जा सकता' के रूप में जकड़ देते हैं। और केवल भविष्य खुला रखते हैं।

लोकस्मृति का एक विलक्षण उदाहरण दक्षिण का 'द्रौपदी उत्सव' पेश करता है। यह एक ऐसा महाभारत है जिसमें पल्लव राजाओं के मुसलमान हमलावरों और विजयनगर के हमलावरों से हुए युद्ध भी शामिल हैं। कहानी कौन हारा और कौन जीता की नहीं है बल्कि वार्ता, समझौता, शांति और संतोष की है। द्रौपदी स्थानीय लोगों की ओर से हमलावरों के साथ वार्ता करके यह सब हासिल करती है। द्रौपदी लोकज्ञान का रूपक है। गांव के बाहर रखे पत्थर के पिण्ड हमलावरों को 'देवत्व' प्रदान करते हैं और गांव वाले अपने लिए शांति और स्वराज हासिल करते हैं। महाभारत एक समृद्ध होती परम्परा है। कला के नये-नये रूप और सार कथानक को भी समृद्ध करते चले जाते हैं। जिस पर समझौता नहीं हो सकता और जिसमें इस खुली परम्परा का आधार है वह है—अपने ज्ञान और समझ के आधार पर लोगों की भागीदारी। इस परम्परा में महाभारत महान योद्धाओं की कहानी न होकर लोगों की कहानी बन जाता है और द्रौपदी उनके आत्मबल का प्रकट रूप।

•

लोकविद्या पंचायत के पाठकों से

- **वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 50/-**
- **वेतन पाने वालों से कम से कम रु. 100/- प्रति वर्ष अपेक्षित है।**
- **आजीवन सदस्यता रु. 1000/-**
- **अपने क्षेत्र के लोकविद्याधरों की समस्यायें, संघर्ष एवं संगठनों के बारे में अवश्य लिख भेजें।**

सम्पर्क फोन : +91-9369124998, +91-9838944822

यूरोप में ज्ञान मुक्ति मोर्चा

30 नवंबर 2011 को प्रसारित

फरवरी 11-13, 2011 को पेरिस में एक ज्ञान मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। यह कदम कई देशों में शासन की विश्वविद्यालयीय नीति के खिलाफ संगठित और आंदोलित छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय जमावड़े में उठाया गया। इस मोर्चे में मुख्य रूप से यूरोप के तथा उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका व एशिया के भी छात्र और असंगठित मजदूर शामिल हैं।

हम सब विश्वविद्यालय को मिलने वाले अनुदान में कटौती, फीस में बढ़ोत्तरी, विश्वविद्यालय के निजीकरण व आर्थिकीकरण तथा कर्ज लेकर पढ़ने की तथा असंगठित व अनियमित मजदूरी करने की मजबूरी के खिलाफ हैं। हम सब स्वतंत्र और स्वायत्त शिक्षा ज्ञान और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही और सबके हित में सामाजिक समृद्धता वापस कायम करने के पक्षधर हैं। इसलिए हमारा कार्यस्थल अंतर्राष्ट्रीय है और हम सब अपने समान दुश्मन के खिलाफ एकजुट हैं।

उपरोक्त पेरिस बैठक के बाद हम बैंकों के खिलाफ और अनुदान कटौतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। स्पेन के बार्सिलोना शहर में और तुनिसिया के तुनिस शहर में बड़ी-बड़ी बैठकें कर चुके हैं, अब हमारी एक वेबसाइट है और एक पत्रिका भी। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है : एक नई दुनिया और एक नया विश्वविद्यालय बनाना। हम जीवित ज्ञान का वैश्विक आंदोलन हैं, हम अपना वर्तमान और भविष्य वापस ले रहे हैं।

हमारा घोषणा-पत्र

1. कटौती का उल्टा संकट का विरोध नहीं है बल्कि जैसा तुनिसिया में हुआ वैसा करना है।
2. पूंजीवादी वैश्वीकरण का उल्टा राष्ट्र-राज्य की सम्प्रभुता में नहीं है बल्कि संघर्षों के वैश्वीकरण में है।
3. कर्ज की व्यवस्था का उल्टा बलिदान (त्याग) में नहीं है बल्कि छात्रों और असंगठित मजदूरों द्वारा कर्ज वापस न करने के अधिकार में है।
4. प्रतिस्पर्धा आधारित प्रवेश का उल्टा सबको प्रवेश देने में नहीं है बल्कि ज्ञान की बुनियादी समीक्षा तथा इस सामाजिक सम्पदा को फिर से सबके लिए हासिल करने में है।
5. अनुदान में कटौती का उल्टा अभी की शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसे में नहीं है बल्कि स्वायत्त शिक्षा और ज्ञान क्षेत्र के स्वयं संगठन के लिए अनुदान के दावे में है।
6. असंगठित मजदूरी का उल्टा संगठित मजदूरी में न होकर बल्कि पक्की न्यूनतम आय और सबके हित में है।
7. भ्रष्टाचार का विरोध भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की मांग में नहीं है बल्कि विरोध प्रदर्शन और साथ में आक्रामक आंदोलन में है।
8. यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक का विकल्प पार्टियों और यूनियनों की प्रतिनिधि व्यवस्था में नहीं है, बल्कि जीवित ज्ञान की स्वायत्तता और उसके ताना-बाना में है।
9. निजी विश्वविद्यालय का उल्टा सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि सबका विश्वविद्यालय है।
10. ज्ञान की अवहेलना का उल्टा ज्ञान की निष्पक्षता की कहानी में नहीं है, बल्कि ज्ञान मुक्ति मोर्चा में है।
11. हमारे पास कुछ बचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया बनाने के लिए है।

•

भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का विरोध

(15 फरवरी 2012 को राष्ट्रीय समाचार-पत्र 'दी हिन्दू' से साभार)

इंग्लैण्ड में लीड्स नाम का शहर है, जहां के विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल में बनाया गया परिसर भारत में किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया पहला उच्च शिक्षा का परिसर है। उनका स्थानीय सहयोगी हैं दैनिक जागरण मीडिया समूह द्वारा स्थापित जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी।

भोपाल प्रदर्शन

इस प्रायास के खिलाफ शिक्षा अधिकार मंच व वामपंथी छात्र-संगठनों के नेतृत्व में भोपाल के कई महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया और लीड्स परिसर के दरवाजे तक जुलूस लेकर गये। पूंजीवादी शिक्षा के प्रारूप का पुतला जलाया और निःशुल्क शिक्षा की मांग की।

विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का कानून अभी बना नहीं है। और इस लीड्स विश्वविद्यालय को भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से कोई मान्यता भी नहीं मिली है। इसलिए यहां से दी गई डिग्री गैर-कानूनी है। लेकिन न राज्य सरकार और न केन्द्र सरकार ही इस विदेशी विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है।

विदेशी शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2010 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने पारित किया है और इसका संसद से पारित होना बाकी है। इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को अर्जी देने के बाद केवल 8 महीनों में भारत में अपने परिसर बनाने की स्वीकृति देने की व्यवस्था है। इनके शैक्षणिक परिसरों पर आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी नहीं होगी। जाहिर है उनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना होगा, आम शिक्षा से कोई वास्ता नहीं होगा।

यह जुलूस भारत में उच्च शिक्षा के बाजारीकरण और निजीकरण के विरोध में संगठित एक बारह दिन के अभियान का हिस्सा था। यह अभियान विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के खिलाफ एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है।

•

यूनान में चल रहा संघर्ष

जिगी रोजेरो, इटली

पश्चिमी देशों के आर्थिक संकट ने यूनान में उग्र रूप धारण कर लिया है। वहां की सरकार यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में एक के बाद एक जन विरोधी नीतियां अपनाती जा रही है। न्यूनतम मजदूरी में 22 फीसदी की कटौती कर दी गयी है और ऐसा आर्थिक पैकेज लागू किया जा रहा है जिससे बेरोजगारों की तादाद में बड़ी बढ़ोत्तरी होगी। सरकार कह रही है कि अगर यह सब नहीं किया गया तो यूनान यूरोपीय संघ के बाहर हो जायेगा, एक अफ्रीका के देश जैसा हो जायेगा और बिजली, खाना, गैस हर चीज की किल्लत होगी, अराजकता फैल जायेगी। यह एक नई राजनीति का उदाहरण बन गया है। यह राजनीति है डराने की। अभी तक आतंकवाद के नाम से डराया जा रहा था, अब उसमें आने वाले दिनों की अराजक तस्वीर जोड़ दी गयी है।

यूनान में लोगों द्वारा सड़कों पर उतरने और शासन द्वारा उनके दमन की खबरें लगातार आ रही हैं। दो साल पहले एथेन्स विश्वविद्यालय के छात्रों का संघर्ष तेजी पर था। तब पुलिस की गोली से एक छात्र की मौत भी हुई थी। तभी से यूनानी शासन की नीतियों का विरोध बड़े पैमाने पर जारी है। अबकी बार 10 से 12 फरवरी के तीन दिन के लिए आंदोलन तय था। 10 और 11 फरवरी को सभी ट्रेड यूनियनों ने 48 घंटे की हड़ताल का आवाहन किया तथा जुलूस निकालकर संसद की ओर प्रस्थान और प्रदर्शन संगठित किया गया लेकिन लोग बड़ी तादाद में नहीं आये। 12 फरवरी को न कोई स्पष्ट आवाहन था न किसी जुलूस का टाइमटेबल प्रसारित किया गया था लेकिन स्वयंस्फूर्त ढंग से बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आये। सबको बस इतना पता था कि दोपहर के बाद से संसद के बाहर के चौराहे पर इकट्ठा होना है। छोटे-बड़े समूहों में चारों तरफ से चलकर लोग वहां आये। इनमें से बहुत से समूह पिछले छः महीनों में बनाये गये हैं। लोग जमा न होने पायें इसके लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यह प्रदर्शन के उस प्रस्ताव नं. 2 के विरोध में था जिसमें तरह-तरह की जन विरोधी कटौतियां सम्मिलित थीं।

यूनानी अर्थव्यवस्था के राजनीतिक नेतृत्व ने इस महासंकट के दौर में वे परिस्थितियां तो पैदा कर ही दी है जिन्होंने यह पूर्ण विरोध का आंदोलन पैदा कर दिया है। अब दो साल हो गये हैं, संगठित राजनैतिक दल इस आंदोलन के नेतृत्व से पूरी तरह बाहर है। लेकिन कोई नया संगठन या नेतृत्व भी उभरता नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है कि एक देश के अंदर की प्रक्रियाओं में हल के रास्ते नहीं हैं। यूरोप के अन्य देशों में इस आंदोलन का विस्तार कैसे हो, शायद यही विचार का विषय बनता है।

(एडु-फैक्टरी नाम के इंटरनेट वार्ता स्थल पर 14 फरवरी को जिगी रोजेरो का एक लेख प्रकाशित हुआ था। यह उसी के आधार पर बनायी गयी हिन्दी प्रस्तुति है।)

•

अमेरिका क्यों डरता है?

विकीलीक्स का खुलासा

विकीलीक्स ने खुलासा किया है कि दुनियाभर में खड़े हो रहे आदिवासियों के संघर्षों और उन संघर्षों का समर्थन करने वालों की जासूसी अमेरिका और कनाडा की सरकारें कराती रही हैं। अमेरिका के प्रशासन में हो रही खबरों की आवाजाही से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका को आदिवासियों के संघर्षों से डर लगने लगा है। पेरु, बोलिविया, वेनीजुएला, गावतेमाला तथा दक्षिणी अमेरिका के और भी देशों व कई अफ्रीकी देशों में हो रहे आदिवासियों के अपने प्राकृतिक अधिकारों के संघर्षों को दबाने के उद्देश्य से अमेरिकी जासूसी की पोल का खुलासा विकीलीक्स ने किया है।

लोकविद्या पंचायत के पन्नों में इन आदिवासी आंदोलनों को जगह दी गयी है। हालांकि ये देश हमसे बहुत दूर हैं और सामान्य तौर पर वहां के घटनाक्रमों पर अपने यहां कोई बहस नहीं होती, लेकिन हम उन्हें तिरस्कृत, बहिष्कृत व शोषित लोगों की एक नई दुनिया बनाने की ओर कदम बढ़ाने वाले संघर्षों के रूप में देखते हैं। भारत के आदिवासी और किसान आंदोलन के साथ उनका एक स्वाभाविक बिरादराना है। ये सब लोकविद्या जन आंदोलन के तरह-तरह के रूप हैं। पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान को चुनौती के आधार पर ये आंदोलन खड़े हो रहे हैं इसीलिए अमेरिका को उनसे इतना डर लगता है।

•

भारतीय किसान यूनियन

16-17 जनवरी 2012 इलाहाबाद की महापंचायत में पारित प्रस्ताव

भारतीय किसान यूनियन द्वारा इलाहाबाद में आयोजित संगम तट पर तीन दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में भारत के किसानों की समस्याओं पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया, जिसमें भारत के लाखों किसानों तथा किसान नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :

1. **फसलों का उचित लाभकारी मूल्य :** फसलों की उत्पादन लागत में पिछले कुछ वर्षों में कई गुना वृद्धि के कारण वर्तमान समर्थन मूल्य से किसान सहमत नहीं हैं। किसानों को उनकी फसलों का उत्पादन लागत तुलनात्मक उचित लाभकारी मूल्य दिया जाय तथा वर्तमान सीजन में गेहूं का मूल्य 2250 रुपये, धान 2200, सोयाबीन 3000, कपास 5000, गन्ना 350, आलू 600 रुपये प्रति कुंतल समर्थन मूल्य घोषित करते हुए सरकार द्वारा खरीद की शत-प्रतिशत गारण्टी दी जाए। समर्थन मूल्य को तय करते समय किसान को कृषि वैज्ञानिक मानते हुए उसी आधार पर किसान की मजदूरी जोड़ी जाए।
2. **खाद की बढ़ी कीमतें :** खाद की कीमतें अचानक दोगुना बढ़ गयी हैं। सरकार द्वारा बढ़ी कीमतें वापिस ली जाये।
3. **कृषि बजट :** भारत कृषि प्रधान देश है, यहां के 60 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हैं। कृषि का बजट भी रेलवे की तरह अलग पेश किया जाये। देश के कुछ राज्यों में सरकारों द्वारा कृषि का अलग बजट बनाया गया है।
4. **बीज कानून :** किसानों का बीजों पर नियंत्रण व सरकारी फार्मों पर बीज का उत्पादन सुनिश्चित किया जाये। मौजूदा बीज विधेयक अप्रासंगिक है, इसमें राज्यों एवं किसानों के अधिकार सुरक्षित किए जाए तथा बीजों के मूल्य निर्धारण की शक्ति सरकार के हाथ में रहे, न कि प्राइवेट कम्पनियों के, ऐसे प्रावधान किए जाएं तथा बीज असफल होने पर कम्पनियों के ऊपर भारी जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ अपराधिक केस दर्ज किये जायं। प्रस्तावित बीआरएआई बिल में बहुत खामियां हैं जिसमें किसान संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी है। अभी आपत्तियों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए इसमें राज्य सरकारों एवं किसानों के हित सुरक्षित रखे जायें तथा इसको जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत लाया जाये।
5. **मुक्त व्यापार समझौते :** कृषि क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते बंद किये जायें। कृषि आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के साथ आयात शुल्क 60 प्रतिशत की जाए। चीन से आयातित सिल्क, प्लाईवुड आदि का आयात बंद किया जाय। वर्तमान में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता चली है उसका अनुमान यह है कि फरवरी में दोनों गुटों के बीच हस्ताक्षर हो जायेंगे। इस समझौते में चिन्ता का विषय मुख्य रूप से यह है कि इसमें भारत के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि इसके बाद 96 प्रतिशत वस्तुओं से (जिसमें कृषि की मुख्य वस्तुएं शामिल हैं) आयातित शुल्क हटा दिया जायेगा, जिससे किसानों को उनकी फसलों के मूल्य नहीं मिल पायेंगे। इसका मुख्य प्रभाव भारत के दुग्ध उत्पादकों, पोल्ट्री फार्म के किसानों पर पड़ने की सम्भावना है। इस समझौते में दूसरा मुद्दा है यूपीओबी-91 जो यूरोपियन देशों में बीज का कानून है और ये बीज कम्पनियों को एकाधिकार देता है। यह समझौता भारत में भी बीज एकाधिकार लाने में बाध्य करेगा।
6. कृषि कार्यों के लिए किसानों को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। डीजल के दामों में भारी वृद्धि होने के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, किसानों को डीजल पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाये।
7. **फसल बीमा योजना :** फसल बीमा योजना में किसान को इकाई माना जाए तथा प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, आग एवं बीजों के असफल होने की दशा में इसका मुआवजा किसानों को दिया जाये तथा किसानों को सरकारी सहायता प्राप्त हेल्थ केयर बीमा योजना के दायरे में लाया जाये।
8. **कृषि ऋण :** किसानों के सभी प्रकार के ऋण (फसली एवं उपकरण) चार प्रतिशत की दर पर उपलबध कराये जायं तथा किसी ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाया जाय तथा उनके सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ किये जायं।
9. **मनरेगा :** मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाये।
10. **असिंचित भूमि :** देश में एक बड़ा हिस्सा असिंचित भूमि का है। आज देश में किसानों की सबसे अधिक आत्महत्या असिंचित भूमि के क्षेत्रों में हुईं। सरकार को असिंचित भूमि हेतु एक विशेष कृषि नीति बनाकर उसे लागू करनी चाहिए।
11. **किसान (महिला एवं पुरुष) :** 60 वर्ष आयु पूरी करने के पश्चात् 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाय।
12. **किसान की विधवा को गुजर-बसर :** 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाये तथा उसके पति द्वारा लिये गए सभी सरकारी व गैर-सरकारी कर्ज माफ किये जायं।
13. **जंगली व आवारा पशु :** किसान को जान व माल की हानि पहुंचाई जा रही है। जंगली जानवरों से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। एक वृहद कार्य योजना बनाकर इनसे निजात दिलायी जाय एवं किसानों के नुकसान की भरपाई की जाये व जान की हानि होने पर पीड़ित किसान को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये।
14. कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए किसान संगठनों से वार्ता कर नई कृषि नीति बनायी जाये।
15. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली :** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) दाल भी उपलब्ध करायी जाये।
16. **देश में चिकित्सा एवं शिक्षा के निजीकरण :** देश में चिकित्सा एवं शिक्षा के निजीकरण को रोका जाये तथा देश में समान चिकित्सा एवं शिक्षा नीति लागू की जाये।
17. **कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि अनुसंधान केन्द्रों :** देश के कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि अनुसंधान केन्द्रों में विदेशी सरकारों एवं कम्पनियों के दखल को समाप्त किया जाये। देश के पारम्परिक बीजों के अनुसंधान के लिए बजट उपलब्ध कराया जाये तथा जैव परिवर्तित बीजों के अनुसंधान को प्रतिबंधित किया जाये।
18. **पारम्परिक खेती बढ़ावा :** पारम्परिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाये तथा उसमें किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

इन प्रस्तावों को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का निर्णय सम्मेलन में लिया गया।

भवदीय,

चौ. नरेश टिकैत	**श्री राजपाल शर्मा**
(राष्ट्रीय अध्यक्ष)	(राष्ट्रीय महासचिव)
श्री बलराम लम्बरदार	**श्री दीवानचन्द चौधरी**
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)	(प्रदेश अध्यक्ष, उ0प्र0)
श्री राजेश चौहान	**श्री जगदीश सिंह**
(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)	(प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश)

भारतीय किसान यूनियन

वाराणसी मण्डल शिविर

विद्या आश्रम पर 4 फरवरी 2012 को भारतीय किसान यूनियन का मण्डल स्तरीय शिविर हुआ। निम्नलिखित चार विषयों पर बात हुई।

1. हर किसान परिवार में एक पक्की नौकरी
2. किसान लागत घटायें, उत्पादन घटायें
3. बिजली का बराबर बंटवारा हो
4. स्थानीय मुद्दे

अपना विचार व्यक्त करने वालों में प्रमुख रहे दिलीप सिंह 'दिली', लक्ष्मण प्रसाद, बाबूलाल मानव, दिनेश पाण्डे, प्रेमलता सिंह, डॉ. चित्रा सहस्त्रबुद्धे, पारसनाथ यादव, शिवप्रसाद, कृष्णकांत, एहसान अली, कृष्ण कुमार, शोभनाथ यादव, विश्वनाथ मास्टर साहब, बबलू कुमार, संत बिलास सिंह और बरईपुर की संघर्षरत किसान महिला व पुरुष।

वाराणसी मण्डल में हर वयस्क को पक्की नौकरी और राष्ट्रीय संसाधनों के बराबर के बंटवारे के सवालों पर पहले से काम चल रहा है। इन मुद्दों पर संगठन के रास्ते खोजे जा रहे हैं।

•

किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटा दुकानदार एक हों

क्योंकि

सूचना युग में कम्प्यूटर-इंटरनेट और वैश्वीकरण मिलकर किसानी, कारीगरी, छोटी दुकानदारी को उजाड़ रहे हैं, मज़दूरी को घटा रहे हैं।

कैसे?

1. **इनके श्रम को बाजार में कम दाम देकर**
2. **इनके ज्ञान यानि लोकविद्या को लूटकर**
3. **शिक्षा को महंगी बना कर व इन्हें नये ज्ञान से वंचित कर**

आइए

1. **लोकविद्या के बल पर जीविका के अधिकार का दावा करें।**
2. **सूचना युग में श्रम और ज्ञान की लूट को रोकने के उपाय खोजें।**
3. **बाजार और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोषण की समझ और विरोध को आकार दें।**

अजय (सिंगरौली) की कविताएँ

विकास का खेल

आओ खेलें, विकास-विकास
दे दो, जो भी है तुम्हारे पास
खेत, मकान, बाग-बगीचा
दुःख मत करना, दुनिया ये फानी है
पानी का बुलबुला ये जिन्दगानी है
कर दो निछावर सर्वस्व अपना देशहित में
लगेगीं विशाल परियोजनाएं, विदेशी कर्जों से
तभी तो 'मेरा भारत महान' विकसित कहलायेगा
आर्थिक ताकत का लोहा दुनिया से मनवायेगा
तुम्हें भी मिलेगा, मुआवजा, पुनर्वास सर्व सुविधा युक्त
पुनर्वास बस्ती में
क्या कहा? नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा विकास
लाये जो पर्यावरण विनाश,
विस्थापन बार-बार
छीनकर संसाधन मेहनती हाथों से,
लोकविद्या के धनी, ज्ञानी जनों से
बनाकर उन्हें, अकुशल ठेका मजदूर।

•

जहां

हमें तो चाहिए जहां ऐसा
हो जिसमें और भी जहां शामिल
न गरजें युद्ध के बादल कहीं पे
रहे निर्णय में तबका हरइक शामिल
न हो पहाड़ वंचनाओं के
रहें सुख-दुःख में सबके, सब शामिल
न हो जहां पे धौंस बहुमत की
नजरिया अल्पमत का हो शामिल
सलामत हो, हरी चूनर धरा की
हो उसमें बर्फ की चादर भी शामिल

•

लोकविद्या की समाजदृष्टि

1. **सभी को अपनी विद्या के बल पर जीवन चलाने का मौलिक अधिकार हो।**
2. **कृषि उत्पाद को जायज़ दाम हो।**
3. **राष्ट्रीय संसाधनों का गाँव और शहर में बराबर का बँटवारा हो।**
4. **घर-घर में उद्योग हो।**
5. **स्थानीय बाजार को संरक्षण हो।**
6. **अधिकतम और न्यूनतम आय में 5:1 से अधिक का अनुपात न हो।**
8. **गाँव-गाँव में मीडिया स्कूल हो।**
9. **उच्च शिक्षा के दरवाजे सबके लिये खुले हों।**
10. **लोकविद्या को विश्वविद्यालय के ज्ञान के बराबर का दर्जा हो।**

बरईपुर, सारनाथ के किसानों का संघर्ष

नंदलाल, बरईपुर, वाराणसी

सारनाथ के पास बरईपुर गाँव के किसानों की 88 बीघे जमीन पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार लोटस पार्क एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये अधिग्रहित कर रही है। आजादी के पहले से इस जमीन पर खेती करने वाले किसान अपनी जमीन बचाने के लिये सरकार से मिन्नते करके थक गये। माह जून 2011 से भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान संघर्षरत हैं। किसान अपने जमीन पर 80 पंचायतें लगा चुके हैं तथा आगे अभी चलाते रहेंगे जब तक कि सरकार का नाजायज नाम जमीन से हट नहीं जाता।

बरईपुर के किसानों का जुलूस

यहां के किसानों के जीविका का मात्र एक साधन जमीन है जो सरकार अधिग्रहित कर रही है। इनके पास जीविका चलाने का कोई अन्य संसाधन नहीं है। अगर ये जमीन सरकार लेती है तो वहां के लोगों की स्थिति रोजगाहीन हो जायेगी और ये किसान रोड पर ठेले- गुमटी लगाते हुये फिरेंगे, और फिर वहां से भी खदेड़ दिये जायेंगे। इसलिये मैं आप सभी कारीगर, छोटे दुकानदार ठेला पटरी व्यवसायी से अपील कर रहा हूँ कि गरीब किसानों की इस लड़ाई में साथ खड़े हो।

कहा जा रहा था कि वाराणसी नगर निगम अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय सारनाथ क्षेत्र में निर्माण करने की योजना बना रहा है जिसके अंतर्गत 18 दिसम्बर 2011को ठेकेदार व मजदूरों के साथ इन किसानों की जमीन पर काम लगाने के लिये आया। इसकी कोई सूचना किसानों को नही थी और न इस तरह के निर्माण की योजना की ही सूचना उनको थी। किसानों ने तुरंत काम रुकवा दिया। उसके बाद 24 दिसम्बर 2011 को प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस अपने चार वाहनों के साथ आई और निर्माण स्थल पर किसानों को जाने से रोकने लगी। शायद यहाँ रैन बसेरा बनाने की योजना बनी थी। ज्योंही किसानों व महिलाओं ने काम को रोकने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया तो पुलिस वालों ने उनको घेर कर रोका। इसके बाद भी महिलाओं ने पुलिस को ढकेलते हुये आगे बढ़कर काम तुरंत बंद करने लिये कहा। प्रशासन की ओर से नींव के लिये खोदे गये गड्ढे में संघर्ष करने वाली गंगाजलि देवी अपनी जान देने के लिये कूद पड़ी। बाद में गंगाजली को बाहर निकालकर महिलाओं ने खुद अपने हाथों में फावड़ा लेकर खोदे गये गड्ढे को पूरी तरह से पाट दिया।

बड़ी संख्या में आई पुलिस से किसानों और महिलाओं ने अपने हाथों में फावड़ा, कुल्हाडी, हंसिया, डण्डा, झण्डा और भारतीय किसान यूनियन का बैनर इत्यादि लेकर घंटों संघर्ष किया। सूचना पाकर अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय किसानों से वार्ता करने के लिये आये और किसानों की बात सुनने के बाद नगर निमग के अधिकारियों से निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। महिलाओं और किसानों के कड़े विरोध के आगे अधिकारियों की एक न चली । अंत में पंचायत में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करके ही आगे कोई निर्णय लिया जायेगा। संघर्ष में सम्मिलित राधा देवी, रमला, कान्ती, चंदा, रमावती, भगवन्नी देवी, सीता, रामजी, प्रेमा,

बरईपुर के किसानों की पंचायत

रामलखन, अमरावती, गंगाजलि, हीरावती, मंजू, धनपत्ती, सुदामा, छुन्नी देवी, मीरा, छेदी, धीरज, राजकुमार,विशुन, रमाशंकर, जोगी, जिउत नारायण, कृष्ण कुमार, नंदलाल,शोभा प्रभुनारायण इत्यादि प्रमुख रूप से थे।

•

पर्यटन का सांटा लोकविद्या पर

प्रेमलता सिंह, वाराणसी

लोकविद्या, लोककला, लोकभाषा से लोकसंस्कृति निर्मित होती है। लोकसंस्कृतियां किसी भी राष्ट्र की रूह होती हैं। विद्या का आधार यदि लोक में है तो कला, भाषा, संस्कृति जीवन्त होती है और समाज व देश भी जिवित होते हैं। विद्या और विद्या आधारित कार्य—उत्पादन, निर्माण और व्यवहार विनिमय से बोली-भाषा विकसित होती है। उनके शब्दों की बुनावट में उस समाज का चित्र और चिन्तन झलकता है। लोकसंस्कृति में मनुष्य सदियों से देशाटन, तीर्थाटन और यायावरी द्वारा शारीरिक मानसिक ऊर्जा और ज्ञान हासिल करता रहा है। जहां वह जाता है वहां की व्यवस्था के अनुसार अपने को ढालता है। न कि उस स्थान विशेष की व्यवस्था में दखल देकर उसे विकृत करता है। तभी तो अपने ही देश में नहीं, दुनिया भर में तरह-तरह की लोक संस्कृतियां विकसित और समृद्ध रहीं हैं। और मानव समाज को ज्ञानी व ओजवान बनाती रही हैं।

पर्यटन लोकसंस्कृति का शब्द नहीं है। यह बाजारवादी व्यवस्था के यान से निकलकर हमारे समाज में पसर रहा है। क्योंकि पर्यटन का विकास लोक की विद्या और उनके समाज के विनाश से होता है। इसमें लोग, लोकविद्या, लोककला, लोकसंस्कृति को मटियामेट करने की योजना निहित होती है। यहां सृजन न होकर पैसे के बल पर खरीदा गया मनोरंजन ही सर्वोपरि होता है। इसे हम विलासिता भी कह सकते हैं।

इस वैश्वीकरण के युग में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है वह लोकविद्या और लोकविद्याधर समाज को नेस्तनाबूद करने की साजिश का ही एक हिस्सा है।

•

लेबै जमीनियां

विजय विनीत

लेबै जमीनियां धुर धुर
अइसे न देखा घूर घूर

अब न सहल जाई मार अउर गारी
अब न बेकार में देखाव बरियारी
हरवा से देबे अब थुर
अइसे न देखा घूर घूर

चले नहीं देब अब कवनो चलाकीं
उहई तोहें चाही जवन बाय अब बाकी
बहुत झोकला अखियां में धुर
अइसे न देखा घूर घूर

चुप नहीं बैठब पाई-पाई के हिसाब होई
तोहरे फरेबवा क मोटा की किताब होई
सुदवा के साधे लेबै मुर
अइसे न देखा घूर घूर

कयदा कानून लील गईला सरकार के
हमारे के रखला हमेशा दुतकार के
तोरी देब तोहरो गरूर
अइसे न देखा घूर घूर

(द संडे इंडियन से साभार)

लोकविद्या जन आन्दोलन
महत्त्वपूर्ण मुद्दे

1. लोकविद्या जीवनयापन अधिकार कानून
2. हर वयस्क को नौकरी-लोकविद्या के आधार पर नौकरी और सरकारी कर्मचारी का वेतन
3. राष्ट्रीय संसाधनों (बिजली, शिक्षा, वित्त ...) का बराबर का बँटवारा
4. स्थानीय बाजार– छोटी दुकानदारी को संरक्षण
5. किसानों की ऊपज को जायज दाम
6. खाद्य व वस्त्र के क्षेत्रों का स्त्रियों के लिये आरक्षण
7. विस्थापन बन्द हो
8. प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समाजों का नियन्त्रण
9. लोकविद्या को ज्ञान की दुनिया में बराबरी का स्थान
10. विश्वविद्यालय की दीवारें गिरें
11. हर गाँव में मीडिया स्कूल
12. लोकविद्याधर समाज की एकता में ही परिवर्तन का सूत्र है

लोकविद्या जन आन्दोलन
वर्ष 2012 के कुछ कार्यक्रम

1. **लखनऊ**
   लोकविद्या विचार पर कार्यशाला, जनवरी 2012
2. **दरभंगा**
   लोकविद्या सम्मेलन, मार्च 2012
3. **विजयवाड़ा**
   लोकविद्या सम्मेलन, मई 2012
4. **सिंगरौली**
   लोकविद्या सम्मेलन, 9 अगस्त 2012
5. **वर्धा**
   लोकविद्या कार्यक्रम, अक्टूबर 2012
6. **इन्दौर**
   लोकविद्या बाजार पर तीन दिवसीय कार्यक्रम, दिसम्बर 2012

बुक पोस्ट

लोकविद्या पंचायत, मासिक समाचार पत्र, विद्या आश्रम (सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007) की ओर से **डा.चित्रा सहस्त्रबुद्धे** द्वारा सम्पादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
प्रकाशन का स्थान : विद्या आश्रम, सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007, स्वामी : विद्या आश्रम
website : vidyaashram.org **Blog :** lokavidyapanchayat.blogspot.com , lokavidyajanandolan.blogspot.com **e-mail :** vidyaashram@gmail.com **Phone :** +91-9838944822
प्रेस : **सत्तनाम प्रिण्टर्स**, एस-1/208 के-1, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, सारनाथ रोड, वाराणसी-221002